वर्ष : 17 ❖ अंक : 47 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शनिवार, 17 सितम्बर 2022

निवेश के लिए भारत सबसे अच्छी जगह : पीयूष गोयल 3

भारत 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का कर रहा है सामना : राहुल गांधी 8

371एफ के खिलाफ प्रदर्शन पर सीएम ने तोड़ी चुप्पी

आरोपियों को गिरफ्तार करने रवाना हो चुकी है पुलिस : गोले

371एफ तथा सिक्किमवासियों की सुरक्षा को सिक्किम सरकार प्रतिबद्ध

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिहार के दो युवाओं द्वारा धरना देकर संविधान के अनुच्छेद 371एफ के तहत सिक्किम को प्रदत्त विशेष दर्जा वापस लेने की मांग उठाने के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने आज कहा कि उनकी सरकार ने उक्त दोनों युवकों को गिरफ्तार करने हेतु गैर जमानती वारंट के साथ कल 15 सितम्बर को राज्य पुलिस के चार अधिकारियों की टीम को नई दिल्ली रवाना कर दिया है।

सिक्किम विधानसभा के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री गोले ने बताया कि 13 सितम्बर को गंगटोक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के साथ राज्य पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई है। मुख्यमंत्री विधानसभा में अपर बुर्तुक के भाजपा विधायक के दिल्ली राम थापा और गंगटोक के विधायक वाईटी लेप्चा द्वारा इस मुद्दे को लेकर उठाये गये सवाल के जवाब में बोल रहे थे। थापा ने राज्य सरकार से इस मामले के मुख्य दोषी की पहचान करने की मांग की।

मुख्यमंत्री गोले ने बताया कि हमें जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बारे में 30 अगस्त को शाम करीब 5 बजे जानकारी मिली। इसमें बिहार के गोपालगंज निवासी सुमंत कुमार और उसके साथी के बारे में शिकायत प्राप्त हुई जो जंतर-मंतर पर धरना देते हुए सिक्किम के अनुच्छेद 371एफ का विरोध कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद सिक्किम सरकार ने राज्य पुलिस को इसकी जांच करने को कहा। 9 सितम्बर को यह जांच पूरी हुई और गंगटोक सदर थाने में आईपीसी 153(ए), 505 तथा 34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

वहीं आरोपी युवक के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री गोले ने सदन में कहा कि बिहार के गोपालगंज निवासी सुमंत कुमार गुप्ता नामक युवक की फेसबुक पर गेजिंग की युवती अमृता छेत्री से जान-पहचान हुई थी। उसके बाद 24 सितम्बर, 2019 को उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी कुछ महीनों तक सिलीगुड़ी में रहे और उसके बाद कार्य की तलाश में चंडीगढ़ चले गये। वहां वे 3-4 महीनों तक रहे। गेजिंग में रह रहे अमृता के माता-पिता से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गोले ने बताया कि दोनों ने स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी।

अमृता के माता-पिता ने बताया कि शादी के बाद दोनों कुछ दिनों तक गेजिंग में भी रहे थे। वहां सुमंत सब्जी बेचने का काम करता था। एक वर्ष बाद सुमंत ने सब्जी बेचना छोड़ कर पेलिंग के एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। दो महीनों तक यह काम करने के बाद अप्रैल 2022 में सिक्किम छोड़ने से पहले उसने गेजिंग में सेल्समैन का भी काम किया था। उसके बाद 6 मई, 2022 के आस-पास उसने अपनी पत्नी का फेसबुक अकाउंट हैक कर सोशल मीडिया में उसके खिलाफ दुष्प्रचार आरम्भ कर दिया। उसके बाद अगस्त में उसने जंतर-मंतर से सिक्किम के अनुच्छेद 371एफ के खिलाफ एक वीडियो बनाकर जारी किया।

मुख्यमंत्री गोले ने सदन को आश्वस्त किया कि जो कोई भी सिक्किम को इस प्रकार बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसे यहां के कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर केवल स्टंटबाजी नहीं कर रही थी, बल्कि आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ केस दायर कर रही थी। अब दोनों युवकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। हम अब इनके पीछे के लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर विरोध जताने वाले लोगों को स्टंटबाजी न करने को कहा। उनके अनुसार इस मुद्दे को तथा सिक्किम के अनुच्छेद 371एफ की असुरक्षा को लेकर प्रचार करने की अधिक जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के दो युवकों के कारण सिक्किम के अनुच्छेद 371एफ को कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अनुच्छेद 371एफ तथा सिक्किमवासियों की सुरक्षा हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांग पारित

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । सिक्किम विधानसभा के छठे सत्र (भाग-3) की आज आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 27314.51 लाख रुपए के दूसरे अनुपूरक अनुदान मांग को पारित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं प्रभारी वित्त मंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) द्वारा सदन में पेश किये जाने के बाद सकल अतिरिक्त व्ययों को पूरा करने हेतु इस दूसरे अनुपूरक अनुदान मांग को पारित कर दिया।

इसके साथ ही आज सदन में मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये दूसरे अनुपूरक अनुदान मांग के लिए सिक्किम एप्रोप्रिएशन बिल, 2022 को भी पारित कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने सिक्किम गुड्स एवं सर्विस टैक्स एमेंडमेंट बिल 2022 भी पेश किया। इस पर विधानसभा के अगले सत्र में चर्चा के बाद वोटिंग करायी जायेगी। वहीं सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार उप्रेती ने सदन में वन एवं पर्यावरण विभाग की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अवसर पर अपने समापन भाषण में सदन के नेता प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने एकदिवसीय इस विशेष सत्र के सफल आयोजन हेतु विधानसभा अध्यक्ष अरूण कुमार उप्रेती, उपाध्यक्ष सांगे लेप्चा के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों व मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिक्किम के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता के साथ हमेशा प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये समसामयिक मुद्दों पर सभी सदस्यों के साथ मिल कर गंभीरता से विचार किया जायेगा। वहीं उन्होंने सिक्किम के वृहत्तर हित में सभी हितधारकों के साथ मिल कर कार्य करने की भी जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार उप्रेती ने भूटिया भाषा में दिये अपने समापन भाषण में सदन के सुचारू आयोजन हेतु सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

भाइचुंग भूटिया ने की राज्यपाल से मुलाकात

इनर लाइन परमिट लागू करने को लेकर सौंपा ज्ञापन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । हाम्रो सिक्किम पार्टी के नेता भाइचुंग भूटिया और बिराज अधिकारी ने राज्यपाल गंगा प्रसाद से मुलाकात कर राज्य में इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन हेतु उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले '371एफ तथा सिक्किम बचाओ' धरना पर बैठे भाइचुंग ने पत्रकारों से कहा कि राज्य के अंदर और कुछ बाहरी राजनीतिक तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक एवं वित्तीय लाभ के लिए सिक्किम की जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे कम जन्म दर होने के बावजूद कैसे राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है।

इस अवसर पर भाइचुंग ने सिक्किम तथा अनुच्छेद 371एफ की सुरक्षा के साथ ही फर्जी कागजातों, फर्जी सीओआई, आरसी, फर्जी मतदाता पहचान पत्र, बढ़ते अपराध, नशीले पदार्थों के सेवन, बरोजगारी आदि समस्याओं के समाधान हेतु इनर लाइन परमिट लागू करने का प्रस्ताव रखा। वहीं अपने धरने के दौरान भाइचुंग भूटिया ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें आगामी 16 अक्टूबर को जन संसद आयोजित करना, जन संसद के प्रस्तावों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप कर सिक्किम के लिए भी ऐसी व्यवस्था की मांग करना, आईएलपी के लिए जागरूकता हेतु सिक्किम यात्रा का आयोजन करना और इसके समर्थन में सामूहिक हस्ताक्षर संग्रह अभियान चलाना शामिल हैं।

भूटिया ने बताया कि जन संसद में सभी लोगों को आमंत्रित कर सिक्किम में आईएलपी के कार्यान्वयन के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने मणिपुर को आईएलपी के तौर पर एक बड़ा उपहार दिया है। ऐसे में सिक्किम में भी इस प्रकार की व्यवस्था की मांग की जाती है।

साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्किम यात्रा के दौरान वह राज्यवासियों को आईएलपी के फायदों से अवगत करायेंगे और उन्हें बतायेंगे कि कैसे यह राज्य में व्याप्त समस्याओं को दूर कर सकती है।

दो दिवसीय ग्रीन टीचर्स क्षमता निर्माण कार्यशाला सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । सिक्किम सरकार के वन व पर्यावरण विभाग के अंतर्गत इनविस हब द्वारा स्थानीय सिडकियांग तुलकु फॉरेस्ट कांफ्रेंस हॉल में दो दिवसीय ग्रीन टीचर्स क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य के 160 स्कूलों के लिए नेशनल ग्रीन कॉख्रस स्कूल ईको-क्लब प्रोग्राम के कार्यान्वयन के एक हिस्से के तौर पर विश्व ओजोन दिवस पर 16 एवं 17 सितम्बर को यह कार्यशाला आयोजित की गयी।

कार्यशाला के पहले दिन मंगन, गंगटोक तथा पाकिम जिलों के 80 और दूसरे दिन नामची, सोरेंग तथा गेजिंग जिलों के 80 शिक्षकों के बैच को शामिल किया गया। मुख्य रुप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर लक्षित ग्रीन स्कूल्स ऑडिटिंग पर आधारित यह कार्यशाला में सेंटर फॉर साइंस एनवायरोमेंट (सीएसई), नयी दिल्ली की सुश्री तुशिता रावत तथा नीरज कुमार रिसोर्स पर्सन के तौर पर शामिल हुए। गौरतलब है कि ग्रीन स्कूल्स ऑडिटिंग सीएसई, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'आपका स्कूल कितना हरित है' शीर्षक ग्रीन स्कूल्स ऑडिट मैनुअल पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।

कार्यशाला का उद्देश्य कार्यान्मुखी परियोजनाओं के माध्यम से स्कूलों में एक सक्षम पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विकसित कर ईको-क्लबों की मदद करना था। एनवायरोमेंट ऑडिट के सफल समापन के बाद सीएसई द्वारा स्कूलों को ग्रीन स्कूल प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे। वहीं इसमें शामिल हुए स्कूलों का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले ग्रीन स्कूल कम्पेटेटिव प्रोग्राम 2022-23 के लिए पंजीकरण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीएसई द्वारा देश के टॉप टेन ग्रीन स्कूलों में (शेष पृष्ठ ०३ पर)

वाराणसी बनी पहली एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी

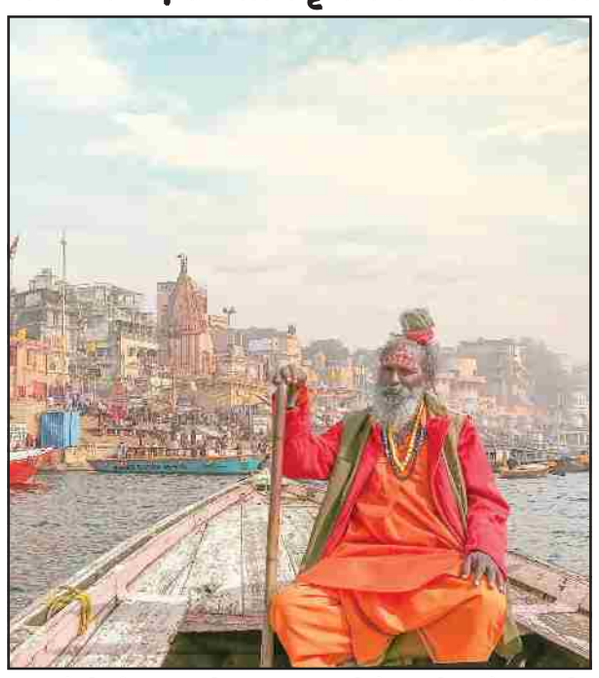

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि वाराणसी शहर को शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। एससीओ के नेताओं ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली 'पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी' के रूप में समर्थन दिया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया ब्रीफिंग में यह जानकारी दी।

क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 2022-23 के दौरान वाराणसी को एससीओ पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए सभी सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह भारत और क्षेत्र के बीच अधिक सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के द्वार खोलता है।

विदेश सचिव ने कहा कि वाराणसी को मिली इस पहचान का जश्न नाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के सहयोग से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्वात्रा ने कहा कि एससीओ ने भारत की पहल पर 'स्टार्टअप' और नवोन्मेष पर एक विशेष कार्य समूह स्थापित करने का भी फैसला किया है।

एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ आठ देशों की सदस्यता वाला एक आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। 9 जून, 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली। इस साल का एससीओ शिखर सम्मेलन शुक्रवार को ही खत्म हुआ है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान गए हुए थे।

एकनाथ सरकार की वजह से गई 1.7 लाख नौकरियां : आदित्य ठाकरे

मुंबई, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाद विपक्ष के निशाने पर उद्योग मंत्री उदय सामंत भी आ गए है। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर परियोजनाओं को गंवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, महाविकास अघाड़ी सरकार ने वेदांत-फॉक्सकॉन परियोजना को लाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार की अज्ञानता ने करीब 1.7 लाख नौकरियों को खो दिया है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन और खनन समूह वेदांता ने संयुक्त रूप से गुजरात के अहमदाबाद में संयंत्र लगा रही है। हालांकि, गुजरात से पहले इस प्लांट को महाराष्ट्र में लगाया जाना था।

1.54 लाख करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर संयंत्र को गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। जिसके बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर संयंत्र के स्थान परिवर्तन को कांग्रेस ने अपशगुन होने का आरोप लगा दिया। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने कहा कि संयंत्र छीना गया है।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी सरकार के लिए यह परियोजना अहम थी। महाराष्ट्र में यह संयंत्र लगना भी लगभग तय था, लेकिन मौजूदा एकनाथ शिंदे ने निवेशकों का विश्वास खो दिया।

सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना कर वेदांता और फॉक्सकॉन चिप्स का निर्माण करेगी। फॉक्सकॉन-वेदांत के संयुक्त उद्यम की डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 60 और 40 प्रतिशत की होगी।

मंगलवार को वेदांत के चेयरमैन ने गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर साइन किया है। वेदांता के चेयरमैन ने कहा कि यह संयंत्र दो साल में उत्पादन शुरू कर देगा। स्थानीय निर्माण से लैपटॉप और टैबलेट की कीमतों में कमी आएगी।

समस्याओं के समाधान के लिए देशवासियों का यात्रा से जुड़ना जरूरी : राहुल गांधी

करूंगपल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए केरल के लोगों का आभार जताया और कहा कि बेरोजगारी, महंगाई तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए देशवासियों का इस यात्रा से जुड़ना जरूरी है।

गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए आज कहा कि देश में भाईचारे को बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जिस तरह से देश में विभाजन की खाई पैदा कर रहे है उसे रोकने के लिए यात्रा का आयोजन जरूरी हो गया था।

उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा ने देश में नफरत फैलाई है और वे नहीं चाहते हैं कि देश में लोग भाईचारे, सद्भाव तथा खुशहाली से रहे। उनका कहना था कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने भी इसी तरह की विभाजनकारी के नीति को अपना देखिए अपना दमन चक्र जारी रखा था।

गांधी ने कहा कि भारत जोडो यात्रा का मक़सद सबको साथ लाना है और देश के सम्मान को विभाजन की साजिश करने वालों से बचाना है। यात्रा के जरिए देश के लोगों में एकता और भाईचारे को बढ़ाना है और इसके लिए कांग्रेस को सभी देशवासियों के समर्थन की जरूरत है।

इस यात्रा में लोगो की ताकत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के सहयोग से ही देश से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है।

गुजरात के पूर्व गृह मंत्री को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 800 करोड़ के घोटाले में हुआ एक्शन

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। दूधसागर डेयरी का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित रूप से 800 करोड़ रूपये की वित्तीय अनियमितता को लेकर गिरफ्तार किये गये गुजरात के पूर्व गृहमंत्री विपुल चौधरी को शुक्रवार को मेहसाणा की एक अदालत ने सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहस्पतिवार को चौधरी को गिरफ्तार किया था और उसने आज विभिन्न आधारों पर चौधरी को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का अदालत से अनुरोध किया। बचाव एवं अभियोजन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए एल व्यास ने पूर्व मंत्री की सात दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर की। अदालत ने चौधरी के साथ ही उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट शैलेश पारीख को भी एक सप्ताह के लिए एसीबी की हिरासत में भेज दिया।

चौधरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ (जीसीएमएमएफ) के अध्यक्ष हैं जो मशहूर अमूल ब्रांड का स्वामी है। वह मेहसाणा जिला सहकारी दूध उत्पादक यूनियन लिमिटेड के प्रमुख भी रह चुके हैं। इसे दूधसागर डेयरी के नाम से भी जाना जाता है।

एसीबी की मेहसाणा इकाई ने दूधसागर डेयरी के प्रमुख रहने के दौरान करीब 800 करोड़ रुपये की आर्थिक अनियमितता में शामिल होने के आरोप में बुधवार को चौधरी एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वित्तीय अनियमितताओं के जरिए धन बनाने के अलावा पूर्व मंत्री ने दूधसागर डेयरी का अध्यक्ष रहने के दौरान अपराध की कमाई 31 कंपनियों के बैंक खातों में डालकर धनशोधन भी किया था। ये कंपनियां इसी स्पष्ट उद्देश्य के लिए बनायी गयी थीं।

एसीबी के अनुसार चौधरी की पत्नी गीताबेन और बेटे पवन को भी प्राथमिकी में सह -आरोपी दर्शाया गया है क्योंकि वे उनके द्वारा प्रवर्तित कुछ कंपनियों में निदेशक हैं। ब्यूरो का कहना है कि चौधरी ने डेयरी का अध्यक्ष रहने के दौरान अपने पद का दुरूपयोग किया और बड़ी संख्या में मिल्क कूलर एवं बोरिया खरीदने में प्रक्रियाओं की अनदेखी की , 485 करोड़ रुपये के निर्माण को मंजूरी दी तथा डेयरी के बाह्य प्रचार अभियान के लिए ठेका देते समय निविदा मार्ग का पालन नहीं किया।

एसीबी ने कहा कि अपनी काली कमाई को वैध दर्शाने के लिए चौधरी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 31 कंपनियां बनायीं और उनमें अपराध से हुए कमाई डाली। चौधरी गुजरात में सहकारिता क्षेत्र के एक जाने माने चेहरे हैं। वह 1996 में शंकर सिंह वाघेला सरकार में गृह मंत्री थे।

अमित शाह आज हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे

नई दिल्ली, 16 सिम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर शनिवार को एक दिन के हैदराबाद दौरे पर जा रहे हैं। इस मौके पर वो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह की शुरूआत करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक सेवा कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और शनिवार को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस में शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ अन्य कार्यक्रम में भी गृहमंत्री भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक सेवा कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित करेंगे।

अमित शाह हैदराबाद में भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहली बार 17 सितंबर के दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रहा है। इसी दिन निजाम के अधीन वाले हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के विलय के बाद देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने यहां तिरंगा फहराया था।

योगी सरकार में अवनीश अवस्थी की धमाकेदार वापसी, मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार

लखनऊ, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। अपर मुख्य सचिव (गृह) के पद से रिटायर हुए आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी पहले से बड़ी भूमिका में लौटे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रशासनिक सलाहकार बनाया है। उनकी नियुक्ति को लेकर शुक्रवार की शाम लेटर जारी हो गया। आदेश के अनुसार उन्हें 28 फरवरी 2023 तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अवनीश अवस्थी पिछले महीने 31 अगस्त को रिटायर हुए थे। तभी से उनके किसी पद पर नियुक्ति की चर्चा हो रही थी।

1887 बैच के आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट से पहले ही सेवा विस्तार की चर्चा थी लेकिन केंद्र से नहीं मिल सका था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री कोई अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं।

अवनीश अवस्थी की पहले से ही मुख्यमंत्री के करीबी और खास अधिकारियों में गिनती होती रही है।

रिटायरमेंट से पहले अवनीश अवस्थी के पास अपर मुख्य सचिव गृह, गोपन, पासपोर्ट, धर्मार्थ कार्य के साथ ही यूपीडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य उन्हीं के सीईओ रहते हुए। कार्यकाल के अंतिम दौर में कुछ महीनों के लिए अवनीश कुमार अवस्थी ने ऊर्जा विभाग की भी कमान संभाली थी। योगी के सीएम बनते ही अवनीश अवस्थी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे थे।

माना जा रहा है कि अब नई जिम्मेदारी में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा विस्तृत हो जाएगी। मुख्यमंत्री का फोकस कानून व्यवस्था के साथ ही यूपी में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रहा है। अब इन सभी पर अवनीश अवस्थी की सीधी नजर होगी और तेजी से कामकाज किए जाएंगे।

पीएम आज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण करेंगे

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। भारत तेजी से अपने औपनिवेशिक हैंगओवर से बाहर निकल रहा है, हाल ही में खुला सेंट्रल विस्टा इसका एक उदाहरण है। इस नए अंतर्निहित विश्वास को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण करेंगे।

एक नया इरादा जो निजी क्षेत्र और सरकार के बीच अपनी बौद्धिक शक्ति को उजागर करने के लिए एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति और तालमेल के माध्यम से क्षमता पैदा करेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की अंतर्निहित भावना को देश भर में एक रसद ढांचा और नेटवर्क बनाने के लिए पेन प्वाइंट के माध्यम से उन्हें नर्सिंग करके नए स्टार्टअप को संभालते हुए सरकार के साथ तालमेल बनाना होगा।

प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन (17 सितंबर) पर रसद लागत को कम करने के लिए इस नई नीति पहल को उपहार देंगे ताकि देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही हो।

यह प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगा। भारत में उच्च रसद लागत एक बाधा के रूप में कार्य करती है और वैश्विक बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

गोयल के अनुसार, देश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 13 से 14 प्रतिशत रसद लागत पर खर्च करता है। जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश, जो अपने विकसित रसद बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं, रसद लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आठ से नौ प्रतिशत खर्च करते हैं।

इसके अलावा, रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां (पीजीए), 37 निर्यात संवर्धन परिषदें, 500 प्रमाणन, 10,000 से अधिक वस्तुएं और 200-बिलियन डॉलर बाजार का आकार है। इसमें 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 रसद सेवाएं, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 166 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), 50 आईटी पारिस्थितिकी तंत्र, बैंक और बीमा एजेंसियां शामिल हैं।

विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के अनुसार, भारत रसद लागत में 44 वें स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों से बहुत पीछे है, जो क्रमश: 14 वें और 26 वें स्थान पर हैं। रसद प्रदर्शन सूचकांक में जर्मनी नंबर 1 पर है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और नई नीति का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10 प्रतिशत की कमी करके इस क्षेत्र में सुधार करना है, जिससे प्रति व्यक्ति पांच से आठ प्रतिशत निर्याता में वृद्धि हो सकेगी।

पीएम मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली नई नीति की मुख्य विशेषताएं होंगी:

डिजिटल सिस्टम का एकीकरण (आईडीएस): इसके तहत सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन, विदेश व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय सहित सात अलग-अलग विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। इन विभागों का अपना डिजिटल डेटा होगा जिसे आईडीएस के तहत एकीकृत किया जाएगा। इससे कम कार्गो आवाजाही में सुधार की उम्मीद है।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप): आईडीएस की तरह ही इस सिस्टम का इस्तेमाल कार्गो की सुगम आवाजाही के लिए भी किया जाएगा।

ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स (ईएलओजी) : इसके तहत नई नीति से नियम सरल होंगे और लॉजिस्टिक्स कारोबार में आसानी होगी।

सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप (एसआईजी): इस सिस्टम का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए किया जाएगा और इससे किसी भी तरह की बाधा को दूर करने में आसानी होगी।

इसके अतिरिक्त, नीति का उद्देश्य कौशल विकास भी होगा। इस नीति से रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।

ग्रामीणों की उपस्थिति ने जनसुनवाई को बनाया सफल

गणेश सिंह 'विशाल'

सिंगरौली, 16 सितम्बर । सरई तहसील अन्तर्गत स्ट्राटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना से प्रभावित गांवों के विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन स्कीम हेतु गुरुवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बासी बेरदहा में जिला प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में मंच का संचालन जिला पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति के प्रशासक डी पी वर्मन द्वारा किया गया जबकि इस मौके पर जिला भू अर्जन अधिकारी और जॉइन्ट कलेक्टर राजेश कुमार शुक्ला भी मौजूद थे वहीं स्ट्राटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से सिंगरौली क्लस्टर हेड बच्चा प्रसाद उपस्थित थे।

तेज बारिश के बावजूद जनसुनवाई में धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना से प्रभावित होनेवाले गावों आमडांड, अमरइखोह, बासी बेरदहा, बेलवार एवं सिरसवाह के लगभग 1000 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद थे। इस जनसुनवाई के दौरान मंच से जहां जिला पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति के अन्तर्गत प्रशासक डी पी वर्मन के द्वारा विस्थापितों/प्रभावितों को दी जानेवाली प्रस्तावित सुविधाओं का जिक्र किया वहीं ग्रामीणों से उनके सुझाव भी मांगे ताकि दी जानेवाली सुविधाओं में उचित संसोधन किया जा सके। गौरतलब है कि जहां कहीं भी कोल परियोजना की शुरुआत होती है, वहां के स्थानीय लोगों को भूअर्जन के लिए समुचित मुआबजा की राशि दिए जाने के बाद उनके विस्थापन के लिए विशेष तौर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की जाती है ताकि उन्हें और उनके परिवार को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके तहत विस्थापित परिवारों के लिए मकान/ख़लॉट की व्यवस्था, विस्थापन हेतु परिवहन खर्च, पशुबाड़ा निर्माण हेतु राशि, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, अनुदान राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, स्वराजगोर के लिए राशि, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान है। इसके अलावा बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, छात्रवृत्ति सुनिश्चित किया जाता है।

साथ ही पुनर्वास कॉलोनी में पक्की सड़क, नालियां, रौशनी की व्यवस्था, शुद्ध पेय जल, उचित मूल्य दूकान, आंगनबाड़ी भवन, हाट बाजार, विद्यालय भवन, सार्वजनिक खेल का मैदान, प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, श्मशान या कब्रिस्तान का निर्माण, मंदिर/मस्जिद की स्थापना और शौचालयों की व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। इस जनसुनवाई में इस प्रोजेक्ट से विस्थापित होनेवाले ग्रामीणों द्वारा कुछ मांगें रखी गईं जैसे विस्थापन हेतु परिवहन खर्च की राशि को बढ़ाया जाए आदि।

अधिकारियों ने प्रभावितों/विस्थापितों को उनकी मांगो पर विचार करने का भरोसा दिलाया। कोल परियोजना शुरू होने पर स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा कौशल विकास के साथ-साथ क्षेत्र की महिलाओं के लिए महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति का संचालन से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता है। पूंजी का प्रवाह सिंगरौली क्षेत्र में होने कारण आसपास के क्षेत्र का विकास हो रहा है। जो भी निजी अथवा सरकारी कम्पनी प्रोजेक्ट लगा रही हैं, उनके द्वारा अपने लाभांश का हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत कोर व वफर जोन के प्रगति के लिए किया जा रहा है।

पर्यावरण अनुकूल खनन के लिए प्रक्रिया सरल बनाई गई है। धिरौली कोल ब्लॉक निजी और सरकारी जमीन मिलाकर कुल 2672 हेक्टेयर में फैला है, जिसकी उत्पादन क्षमता 6.5 एमटीपीए है। जनसुनवाई के दौरान कई बुजुर्ग ग्रामीणों के साथ-साथ धिरौली प्रोजेक्ट हेड राज किशोर सिंह, सुलियारी प्रोजेक्ट हेड अमरेंद्र कुमार और एच आर क्लस्टर हेड विनोद यादव भी मौजूद थे। खदान के शुरू होने से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्थान होगा जिससे तेजी से सामाजिक विकास होगा।

मैनुफैक्चरिंग हब के लिए जाना जाएगा भारत : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा विश्व में मैनुफैक्चरिंग हब के लिए जाना जाएगा भारत। भारत के युवा और प्रतिभाशाली लोग हमें स्वाभाविक रूप से कम्पेटिटिव बनाते है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की आशा है।

पीएम मोदी ने कहा, 'आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है।'

पीएम बोले, 'एसईओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेसिलिएंट और डायवर्सिफायड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिज में से एक होगी। हम प्रत्येकसेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट अप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा यह अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है हम एससीओ सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।'

ईडी के बाद अब सीबीआई ने शिक्षा घोटाले में पूछताछ के लिए पार्थ चटर्जी को हिरासत में लिया

कोलकाता, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सीबीआई ने चटर्जी को हिरासत में लेने के लिए अलीपुर जिला अदालत से अनुरोध किया था। इस कथित घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चटर्जी और उनकी कथित निकटतम सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गत 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

इस दौरान ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपये नकद, सोना-चांदी, आभूषण और सम्पत्ति दस्तावेज बरामद किये थे। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखे गये पूर्व मंत्री को अलीपुर जिला अदालत की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष शुक्रवार को पेश किया गया था। उन्हें जांच के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत की मांग के मद्देनजर अदालत के निर्देश पर पेश किया गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री को पूछताछ के लिए 14-दिन की हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया है।

चटर्जी के वकील ने विशेष न्यायाधीश से अपने मुवक्किल की उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाने का अनुरोध किया। पूर्व मंत्री ने कहा है कि वह प्रतिदिन 28 दवाएं लेते हैं। चटर्जी ने मामले में खुद को निर्दोष करार देते हुए कहा कि वह भर्ती घोटाले के हर रोज के मामले से वाकिफ नहीं हैं। चटर्जी को जांच एजेंसी की हिरासत में सौंपने का अदालत से अनुरोध कर रही सीबीआई के वकील ने दलील दी कि यदि पूर्व मंत्री को अभी जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे एसएससी घोटाले की जांच प्रभावित होगी। सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएससी भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। उच्च न्यायालय इस जांच की निगरानी भी कर रहा है।

दो दिवसीय ग्रीन टीचर्स ......

शामिल होने के लिए सिक्किम के कई स्कूलों को पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा वन व पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य के सभी 856 ईको-क्लबों को वार्षिक 5000 रुपए की सहायता राशि के साथ ईको-क्लब हैंडबुक, ग्रीन स्कूल मैनुअल, सफाई उपकरण आदि प्रदान किये जाते हैं।

इस कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर एनविस निदेशक सह एनजीसी-सिक्किम के नोडल अधिकारी बीबी गुरुंग, एनविस की संयुक्त निदेशक श्रीमती कुसुम गुरुंग तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। इसका परिचालन एनविस के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी राजेन प्रधान ने किया।

भारत में जो बिकेगा वह यहीं बनेगा- आत्मनिर्भर अभियान में राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने एक और अहम संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने विनिर्माताओं के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि 'यहां जो बिकेगा वह यहीं बनेगा' और इस मंत्र पर चलते हुए आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बनकर उभरेगा।

सिंह ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'आज भारत 'वैश्विक उम्मीद' का केन्द्र है, क्योंकि इस देश में अवसरों का भंडार है, विकल्प की भरमार है और खुलेपन का विस्तार है। भारत में जन, मन और सारा तंत्र खुलेपन का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत खुले मन से नए दरवाजे खोलने का नाम है। हमारे दरवाजे बंद नही हो रहे बल्कि और खुल रहे हैं बस शर्त इतनी है कि विनिर्माण हमारे घर पर ही करें।'

भारत के बड़े बाजार के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'यहां जो मौका है वह कहीं और नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि हमारे लिए, बनाना है तो इसी देश में बनाइए। सीधे शब्दों में कहा जाए, कि 'भारत में जो बिकेगा वह यहीं बनेगा'।

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग साढ़े आठ वर्षों में भारत ने विश्व में जो प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित किया है वह अभूतपूर्व है। 'मुझे विश्वास है कि अगले दस वर्षों में भारत जापान को पीछे छोड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी। भारत ऐसी महाशक्ति बनेगा जहां धन भी होगा और बुद्धि भी होगी।'

सिंह ने आजादी के समय देश का नेतृत्व करने वाले दलों पर आरोप लगाते हुए, कहा कि उन्होंने देशहित को सर्वप्रथम नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यदि आजादी के समय से ही जिन लोगों के हाथ इस देश की सत्ता रही उन्होंने राष्ट्र प्रथम की नीति पर काम किया होता तो भारत दशकों पहले ही एक विकसित देश की कतार में खड़ा होता।

उन्होंने कहा कि यह सही है कि भारत उस समय कमजोर था, गरीब था, इसलिए, उसे विकास की राह पर रफ्तार पकड़ने में समय लगा। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1960 में वह लुढ़क कर आठवें और 1970 में 9वें और 1980 में तो वह टाप टेन की सूची से ही बाहर हो गई। नब्बे के दशक में थोड़ा सुधार हुआ मगर टॉप टेन की रैंकिंग में तब भी भारत बाहर ही था।

उन्होंने कहा, 'दुनिया की 'टाप टेन' अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वापसी पिछले दस वर्षों में हुई जब वह नवीं पायदान पर आया। आज 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 'टॉप फ़ाइव' इकोनोमी में पांचवी पायदान पर है।'

देश में विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'इस देश में एक वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर बने इस दिशा में काम चल रहा है। आज इस तरह की इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन संभवत: चीन को छोड़ कर कहीं और नहीं है। वहां भी अभी स्लो डाउन चल रहा है।'

उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बड़े-बड़े विकसित देश, रिकार्ड महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की महंगाई की दर बेकाबू नही होने पाई है। 'आज ब्रिटेन में 18 फीसदी के आस-पास महंगाई है। अमेरिका में यह महंगाई दर 9-10 फीसदी है। इन देशों की जनता ने दशकों से महंगाई के दर्शन नही किए थे।

जबकि भारत में महंगाई की दर अगस्त में 7 फीसदी रही है। भारत जैसे विकासशील देश में महंगाई पर काबू रखने और आर्थिक सुधार करने का ही परिणाम है कि आज विदेशी निवेशक भारत की तरफ, दौड़े-दौड़े चले आ रहे हैं।

बिहार के लिए सियासी मुद्दा बनकर रह गया 'विशेष राज्य का दर्जा'!

पटना, 16 सितम्बर (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से अलग होने के बाद एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को छेड़ दिया है। बिहार की राजनीति में अब यह कहा जाने लगा है कि विशेष राज्य का दर्जा केवल सियासी मुद्दा बनकर रह गया।

वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है, लेकिन अब कहा जाने लगा है कि सभी दल सुविधानुसार इस मांग के जरिए इस मुद्दे को हवा देकर बिहार के विकास के जरिए शुभचिंतक बनने की कोशिश करते हैं।

मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुरुवार को कहा था कि वह बिहार को शुरू से ही विशेष राज्य दर्जा देने की मांग करते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस मांग को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है और वह इसकी निरंतर मांग करते रहे हैं, इसके लिए अभियान तक चलाया है और सरकार के स्तर से भी मांग की गई है।

उन्होंने कहा की अगर इन लोगों की जगह पर सरकार बनाने का मौका मिला और जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट होकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ें और सरकार बनी तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं अन्य पिछड़े राज्यों को भी वह सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी।

इधर, नीतीश कुमार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे पर दिए गये बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि जब पूरे देश से विशेष राज्य का दर्जा वाला शब्द सदा के लिए समाप्त कर दिया गया तब नीतीश इस मुद्दे करने का नाटक कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वे स्वयं केंद्रीय मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विशेष राज्य का दर्जा 10 वर्षों के लिए अलग हुए कमजोर प्रदेशों को दे रहे थे, तब नीतीश ने यह होने नहीं दिया। उनके पूर्व सांसद एनके सिंह 15 वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे, जिसकी अनुशंसा 2021 से 26 तक के लिए है, तब भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा।

डॉ जायसवाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गई है। आज सभी राज्यों को केंद्र की राशि से 10 फीसदी हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है। नरेंद्र मोदी के जीएसटी लागू करने से औद्योगिक राज्यों को जहां घाटा हुआ है वहीं बिहार जैसे उपभोक्ता राज्यों को जबरदस्त फायदा हुआ है क्योंकि अब टैक्स, जहां सामान बिकता है उसी राज्य को मिलता है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से बड़े राज्य मध्य प्रदेश से 32,000 करोड़ रुपए बिहार को केंद्रीय सहायता के रूप में हर वर्ष ज्यादा मिलता है। एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गति शक्ति योजना बिहार को मिली है। अगर यह ईमानदारी से लागू किया जाए तो

लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वैसे देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कोई नई नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर यहां राजनीति भी खूब हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य में जदयू इस मांग को बिहार की जनआकांक्षा से जोड़कर इसे राज्य के हर तबके के पास पहुंचाने में सफल रहा है। जदयू ने इस मांग को लेकर न केवल बिहार में, बल्कि दिल्ली तक में अधिकार रैली निकाली थी।

निवेश के लिए भारत सबसे अच्छी जगह : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। अमेरिका में एबीसी - यानि एनीथिंग बट चाइना - को व्यापक समर्थन मिल रहा है। भारत तेजी से अमेरिकी व्यापार के लिए पहली पसंद का देश बनता जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जहां तक अमेरिकी कारोबार का सवाल है तो भारत पहली पसंद है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आईएएनएस से कहा, भारत, अमेरिका के लिए विशेष स्थान रखता है। वास्तव में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है ● कृषि सामान, सेवाएं ● वे हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं। कारण स्पष्ट हैं - राजनीतिक स्थिरता, तकनीक और डिजाइन में उभरती शक्ति और विशाल उपभोक्ता बाजार। वे इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी भारत में उद्योग स्थापित करना चाहती है जिसमें 200,000 से अधिक लोगों को काम पर रखा जाएगा। फोकस सेमी कंडक्टर, अत्याधुनिक आर एंड डी और डिजाइन की ताकत पर है।

भारत को लेकर इतनी उम्मीद क्यों है ? जाहिर है, भारत की बढ़ती जीडीपी, जो सभी को अपनी ओर खींच रही है। गोयल ने तर्क दिया कि विश्व व्यापार संगठन के दौर में भारत के कोविड प्रबंधन, वैक्सीन दक्षता को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

मैं कई देशों के मंत्रियों से मिला और उन्होंने भारत के पूरे इकोसिस्टम की प्रशंसा की, जिसे भारत ने कोविड के दौरान बनाया। इसके अलावा, भारत ने इस कठिन समय में किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ा। यहां तक कि हमारी डब्ल्यूएफएच ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इसकी बढ़ी हुई ताकत की भी सराहना की गई। कभी-कभी, मुझे नहीं लगता कि हम भारतीयों को अपनी असीम क्षमता का एहसास है। इस पर विदेशी कब्जा कर रहे हैं। हां, भारत में लागत कम है, लेकिन वे भारत को उस स्तर पर देख रहे हैं जिसे हम समझने में असमर्थ हैं। यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है।

गोयल ने यह भी कहा कि भारतीय श्रम की अब सबसे अधिक मांग है। उन्होंने कपड़ा राजधानी तिरुपुर की हालिया यात्रा का जिक्र किया जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे तिरुपुर अगला बांग्लादेश

बन सकता है।

उन्होंने कहा, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश बन सकते हैं, मैंने उन्हें बताया और सोचिए उनकी प्रतिक्रिया क्या थी - हमें 50,000 से 100000 लोग भेज दीजिए और फिर देखिए कैसे उनका ऑपरेशन बढ़ता है।

विदेशी निवेशक चाहते हैं कि व्यापार करने में आसानी हो, लेकिन समान रूप से हमें अपने स्किल और तकनीक को तेज गति से अपनाना होगा, गोयल ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में फॉक्सकॉन / वेदांता सौदे से पता चलता है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना और इस तरह के सभी निवेशों की आधारशिला के लिए संघीय भावना का डबल इंजन होना चाहिए - सहयोग और प्रतिस्पर्धा।

उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों के अनुकरणीय कार्य करने से अमेरिका में भारतीय उद्यमिता फली-फूली है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका में उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय से विस्तार से बात की और उनसे कहा, भारत के पास लोगों की एक बड़ी फौज है। हमारे युवा, सबसे बड़ा अवसर हैं और उनमें से सभी इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े हैं। हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे में यह हमारे लिए सोचने का एक महत्वपूर्ण समय है कि हम अगले 25 वर्षों में भारत को कहां देखते हैं। अमृत काल के अगले 25 साल, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा को परिभाषित करेगा। हमारा लक्ष्य निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनना है।

पीएम केयर फंड : दिल्ली एचसी ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को स्टेट घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगते हुए कहा: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

मामले की अगली सुनवाई अगले साल 31 जनवरी को होगी।

पिछली सुनवाई में भी, अदालत ने पीएमओ सचिव द्वारा दायर एक पेज के हलफनामे के जवाब के बाद केंद्र से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा था।

अदालत सम्यक गंगवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि फंड संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट है और इसे भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री, इसके संक्षिप्ताक्षर सहित, वेबसाइट पर इसके नाम के उपयोग करने से रोकने के लिए है।

केंद्र के पहले के सबमिशन के अनुसार, पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया था कि कोई भी सरकारी पैसा पीएम केयर्स फंड में जमा नहीं किया जाता है और इसमें केवल बिना शर्त और स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किए जाते हैं।

पीएमओ द्वारा दायर एक पूर्व हलफनामे में कहा गया है, 'यह दोहराया जाता है कि ट्रस्ट का फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है।'

NAME CHANGED

JC-No. 671401 W SUB (Hony Lt.), Mahabir Singh Rawat 517 ASC Bn, c/o 99APO, Vill-Lekuli, Post- Kilbokhal, Dist. - Pouri Garhwat, State-Uttarkhand, Pin– 246170, have changed daughter name from Suman to Suman Rawat in my service record. Aff ser A-244065 Date: 14.09.2022

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR VULTURE EVENING

FRIDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:194 DrawDate on:16/09/22

1st Prize ₹1 Crore/- 73G 57042

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 57042 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

04913 15202 20457 21926 22400 29723 31979 36045 62466 91431

3rd Prize ₹450/-

0095 1130 1257 2393 2518 3061 3884 5015 5765 7074

4th Prize ₹250/-

0347 0694 1828 1855 2616 3680 4419 5841 6154 7344

5th Prize ₹120/-

0256 0423 0450 0841 0849 0914 0963 1177 1363 1375
1446 1447 1689 1703 1721 1748 1782 1792 1932 1957
2096 2151 2240 2428 2604 2706 2716 2763 2767 2853
2869 3153 3232 3251 3395 3640 3661 3731 3754 3786
4277 4284 4399 4423 4446 4524 4575 4601 4671 4974
5133 5190 5285 5291 5339 5412 5435 5530 5645 5860
5924 5967 6121 6217 6352 6402 6411 6417 6513 6603
6617 6618 6688 6751 6772 6896 6903 6921 6974 7032
7253 7358 7368 7616 7737 7755 7877 7924 8171 8283
8374 8580 8873 9059 9125 9130 9237 9454 9701 9907

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR HOOGHLY MORNING

FRIDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:94 DrawDate on:16/09/22

1st Prize ₹1 Crore/- 47G 00836

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 00836 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

03291 08010 08039 17048 39269 50162 65744 78789 84601 96731

3rd Prize ₹450/-

2594 2864 3025 4200 4573 5323 5805 5883 8234 8578

4th Prize ₹250/-

0617 1187 1570 1819 2643 3449 5223 6314 8673 9230

5th Prize ₹120/-

0206 0349 0487 0490 0614 0653 0659 0664 0665 0707
0710 0803 1079 1273 1297 1508 1592 1621 1633 1747
1841 1967 2016 2143 2421 2536 2686 2721 2741 3227
3266 3352 3990 4218 4242 4257 4361 4445 4503 4539
4784 4823 4826 4893 4970 5011 5081 5089 5146 5163
5200 5418 5539 5626 5711 5722 5899 6090 6092 6197
6700 6813 7172 7186 7336 7475 7505 7514 7606 7641
7790 7804 7864 7885 7949 7996 8092 8123 8181 8204
8272 8322 8370 8421 8471 8899 9056 9091 9265 9275
9429 9443 9601 9602 9676 9689 9707 9723 9901 9953

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR EARTH FRIDAY

WEEKLY LOTTERY

Draw No:94 DrawDate on:16/09/22

1st Prize ₹1 Crore/- 97E 02511

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 02511 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

07841 12751 19024 33320 34127 37085 54907 60425 81761 95401

3rd Prize ₹450/-

0159 0338 2657 3382 3398 5373 6529 7036 9308 9715

4th Prize ₹250/-

0055 1880 1990 2065 5622 5646 5687 6035 6089 7194

5th Prize ₹120/-

0201 0377 0509 0878 0934 1132 1134 1225 1263 1315
1413 1564 1820 1835 1895 1944 2070 2073 2121 2156
2233 2414 2477 2529 2690 2800 2887 2913 2956 3051
3525 3538 3539 3602 3692 3697 3702 3904 4202 4260
4281 4467 4503 4574 4665 4682 4684 4922 4968 5270
5582 5737 5883 6020 6085 6178 6503 6519 6562 6653
6760 6884 6937 6951 6973 7182 7317 7347 7366 7446
7505 7540 7661 7940 7944 7960 8184 8309 8468 8470
8524 8575 8603 8648 8661 8753 8799 8954 9017 9057
9073 9146 9224 9271 9357 9426 9485 9486 9568 9919

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

स्टूडेंट्स को तंग न करें

रूसी हमले के बाद यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स की समस्याएं जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। बीच में ही पढ़ाई छोड़ आने को मजबूर इन स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वे अपना कोर्स कैसे पूरा करें। उसके बगैर उनका कोई करियर नहीं हो सकता। लंबे इंतजार के बाद इस महीने नैशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) से उन्हें यह इजाजत मिली कि वे यूक्रेन के विश्वविद्यालयों से अपना ट्रांसफर दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में करवा सकते हैं। यह उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन सिर्फ कागजों पर। इसे अमल में लाने के लिए जरूरी है कि यूक्रेन के विश्वविद्यालय इनका ट्रांसफर करें और उन्हें उनके ओरिजिनल दस्तावेज सौंपें। मगर इन विश्वविद्यालयों का रवैया न सिर्फ बेतुका बल्कि अमानवीय है।

कई संस्थानों ने इन स्टूडेंट्स का ट्रांसफर का अनुरोध सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अब देश में हालात ठीक हैं और इसलिए उन स्टूडेंट्स को वापस आकर कॉलेज जॉइन करना चाहिए। जिन यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट्स ने ऐसा मनमाना आदेश जारी नहीं किया और इच्छुक स्टूडेंट्स का ट्रांसफर करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है उनकी तरफ से भी ऐसी ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं जिन्हें पूरा करना मौजूदा हालात में लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के लिए, कई यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि इन स्टूडेंट्स को तब तक उनके ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए जा सकते, जब तक वे लाइब्रेरी से ली गई किताबें और कॉलेज की अन्य संपत्ति खुद आकर वापस नहीं करते। सचाई यह है कि जिन स्थितियों में ये स्टूडेंट्स वहां से स्वदेश लौटे उनमें यह संभव ही नहीं था कि वे सारा सामान साथ ले आते। मिनिमम सामान के साथ जान बचाते हुए निकल आना ही उस समय संभव था और सबने ऐसा ही किया भी। ये स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं कि सारा सामान वे ज्यों का त्यों हॉस्टलों में छोड़ आए। अब कहां वे किताबें ढूंढें और कैसे वापस करें। बाकी औपचारिकताओं के लिए भी स्टूडेंट्स से खुद वहां आने के लिए के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे रूस-यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जाहिर है, इन यूनिवर्सिटीज का मकसद ट्रांसफर मामले को अधिक से अधिक अटकाए रखना है ताकि स्टूडेंट्स उनके यहां बने रहें और यूनिवर्सिटी को उनसे होने वाली कमाई बंद न हो। लेकिन यह वक्त ऐसा है जिसमें यूनिवर्सिटी को अपनी कमाई से ऊपर उठकर स्टूडेंट्स के भविष्य के लिहाज से सोचना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी स्वेच्छा से ऐसा नहीं करतीं तो राजनयिक और जरूरत पड़े तो राजनीतिक स्तर पर भी यह मसला उठाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका सरल और व्यावहारिक उपाय जल्द से जल्द निकले।

जनभागीदारी लोकतंत्र की आधारशिला है- जन शक्ति में पीएम मोदी की अटूट आस्था

जे.पी. नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
बीजेपी

''हमारी ताकत लोगों की ताकत में है। हमारी ताकत हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में निहित है'' - प्रधानमंत्री मोदी

जनभागीदारी की अवधारणा, जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों की भागीदारी है, का मतलब है नीतियों के कार्यान्वयन में सभी की सामूहिक भूमिका।

भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को लागू करने का केंद्रीय पहलू लोगों की शक्ति का उपयोग करना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान जनता को काम करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित करके, कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोक कर, सरकार के लिए मुद्दे तय करके और दूसरों को शासन की मदद करने के लिए प्रेरित करके इस जनशक्ति के उपयोग के लाभों को प्रत्यक्ष दिखाया है।

संवाद: बेहतर शासन का एक उपकरण

जन संवाद की लगातार प्रक्रिया के बिना जनभागीदारी अधूरी है। वास्तविक सहभागी शासन का सार जमीनी वास्तविकताओं को समझने के लिए लोगों के साथ नियमित बातचीत करने की प्रक्रिया पर निर्धारित होता है, जिसके बाद मुद्दों के विश्लेषण और उनसे निपटने के लिए सुझावात्मक उपाय पर आधारित नीतियां कागजों पर आती हैं। आदर्श रूप से नीति के कार्यान्वयन और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया के बाद, लाभार्थियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर नीति लागू की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों और सरकार के बीच इस निरंतर संवाद को विभिन्न माध्यमों से बनाए रखने और लोगों के जीवन को आसान बनाने का व्यापक ध्यान रखा है। इसका एक सटीक उदाहरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि को मजबूती देने के लिए 2016 में फसल बीमा की दो प्रमुख योजनाओं को मिला कर फसल बीमा योजना लागू की थी जिसे 2019-2020 में फिर से लॉन्च किया गया था। यह संशोधित योजना विभिन्न ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तरीकों से मिली किसानों की प्रतिक्रियाओं की अनूठी परिणति है। यह किसानों की विभिन्न चिंताओं का ध्यान रखती है। और यह परिवर्तनकारी बदलाव में संवाद की शक्ति का सच्चा उदाहरण है।

जन नेतृत्व वाले विकास का युग

प्रधानमंत्री मोदी जनता को अंतिम मील तक जाने के लिए प्रेरित करने के अपने प्रयासों में निर्विवाद रूप से सफल रहे हैं। कागज पर बनी नीतियों को हकीकत में बदलने के लिए लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि अनेक बार उनके आह्वान पर समर्थन दिया है। आंकड़ों में देखें तो योजनाओं की संख्यात्मक और डेटा-संचालित सफलता सपाट या एक-आयामी लग सकती है। मगर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित और क्रियान्वित योजनाओं की सुंदरता उनकी बहुआयामी होने में है। उनके शब्द इस बात का प्रमाण हैं कि वे लोगों के समग्र विकास के संदर्भ में सोचते हैं और समग्र विकास की यात्रा में किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं।

नेता के रूप में नीतियों और उनके लाभों को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने का उनका प्रण प्रधानमंत्री की दृष्टि और शासन में हमेशा और लगातार परिलक्षित होता रहा है। उदाहरण के लिए खुले में शौच के मुद्दे को लें, जिसे प्रधान मंत्री के रूप में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधान मंत्री मोदी ने उठाया था। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए कहा और एक ऐसा जन आंदोलन बना जिसकी परिणति देश में एक लाख से अधिक ओडीएफ ख़ल्स (खुले में शौच से मुक्ति) गांवों में हुई। केवल 60 महीनों में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने में सफलता पाई गई। यह एक ऐसा कारनामा है जिसे देख कर दुनिया चकित है। भले ही यह सिर्फ एक स्वच्छता मिशन की तरह लग सकता है, मगर इसने महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा भी सुनिश्चित की है, कई बच्चों की जान बचाई है और कई लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोका है।

जल जीवन मिशन का एक और उदाहरण लें, अकेले जिसने अब तक गांवों में 10 करोड़ से अधिक नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित किए हैं। उनके अपने शब्दों में, 'जल जीवन मिशन की सफलता आधारित है: लोगों की भागीदारी, सभी हितधारकों के साथ साझेदारी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सभी संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग पर।' जनता के जीवन की इस मूलभूत आवश्यकता का का पूरा होना अब एक वास्तविकता है। महिलाओं को पानी लाने के लिए अब घंटों चलने की आवश्यकता नहीं है, दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगा है, साथ ही ग्रामीण परिवारों का जीवन आसान हुआ है।

एक और प्रमाण और देखें। केवल 18 महीनों 200 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड में हासिल करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, लेकिन हमने इसे हासिल की। हालांकि यह कई लोगों के मिलेजुले प्रयासों का फल था मगर इसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिन्हें अपने लोगों में अविश्वसनीय और अटूट विश्वास था। और लोगों ने उनके दृढ़ संकल्प की भावना में भरपूर सहयोग दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित एक अन्य महत्वपूर्ण जन आंदोलन हमने महामारी के दौरान देखा जब उन्होंने नागरिकों से कर्फ्यू का सम्मान करने का आग्रह किया, स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की और सबसे आगे लड़ने वालों की सराहना करने के लिए दीयों के प्रकाश का आह्वान किया जिसका देश भर में जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकटीकरण हुआ। सरकार द्वारा नागरिकों को टीकाकरण के लिए कोई निर्देश नहीं देने के बावजूद, लोगों ने बेहतर विकल्प चुनने का वादा निभाया। इसी प्रकार जो लोग वहन कर सकते थे, उन्होंने स्वेच्छा से एलपीजी और रेलवे टिकट पर सब्सिडी छोड़ दी, जबकि वास्तविक सब्सिडी नहीं हटाई गई थी। इस प्रकार जब उन्हें कहा गया तो 'इसे छोड़ दें' तो उन्होंने आह्वान को मान लिया। यदि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली जनभागीदारी की शक्ति का उदाहरण नहीं हैं, तो क्या हैं?

भागीदारी से समृद्धि तक

मन की बात, जिसे व्यापक रूप से (और ठीक भी है) एक बड़ी सफल सामाजिक क्रांति करार दिया गया है, उसका आधार भी जनभागीदारी ही है। इसका प्रत्येक एपिसोड हर व्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के अटूट विश्वास को हर महीने याद दिलाता है।

स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला उल्लेखनीय जन आंदोलन वोकल फॉर लोकल लोगों में जागरूकता पैदा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक लंबा सफर तय कर चुका है। इस जन आंदोलन ने कई छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया है, देश के दूरदराज के हिस्सों में स्टार्टअप को बनाए रखने में मदद की है और पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने में भी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी का स्थानीय खिलौनों के बारे में मुखर आह्वान एक अनूठी घटना है जो खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भरता के मिशन का हिस्सा है।

'मैं 5 से 7 साल की उम्र के छोटे बच्चों को सलाम करना चाहता हूं। देश की चेतना जाग उठी है। मैंने अनगिनत परिवारों से सुना है कि 5-7 साल के बच्चे अपने माता-पिता से कहते हैं कि वे विदेशी खिलौनों से नहीं खेलना चाहते। जब 5 साल का बच्चा ऐसा संकल्प करता है, तो यह उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है,' प्रधानमंत्री मोदी, स्वतंत्रता दिवस, 2022।

प्रधानमंत्री मोदी 2020 से स्टार्टअप्स से वैश्विक टॉय हब बनने की उपलब्धि हासिल करने और देश में टॉय क्लस्टर स्थापित करने में सहायता करने का आग्रह करते रहे हैं।

अब 2022 में देखें देश में अनेक खिलौना समूह आ गए हैं, भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित खिलौनों के विकास के लिए नवीन विचारों को क्राउडसोर्स करने के लिए 'टॉयकैथॉन' जैसे आयोजनों ने गति पकड़ी है, खिलौनों को बीआईएस (भारतीय प्रमाणन ब्यूरो) मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाना सभी निर्माताओं के लिए अनिवार्य हो गया है जिससे कई चीनी प्रतिस्पर्धी समाप्त हो गये हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019-22 में निर्यात में 70 प्रतिशत की वृद्धि और आयात में 61 प्रतिशत की कमी हुई है। इस तरह के सभी उपायों की परिणति भारतीय खिलौनों के निर्यात में हुई है जो अथाह ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और यह इस बात का प्रमाण है कि एक दृढ़ राष्ट्र क्या कुछ कर सकता है।

'लोकतंत्र केवल एक सरकार को पांच साल के लिए अनुबंध देना नहीं है। वास्तव में यह जनभागीदारी है।'- प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों पर जो अटूट विश्वास लगातार दिखाया है, उसके बार-बार अकल्पनीय सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। जब नीतियां अंतिम मील तक पहुंचती हैं, तब लोकतंत्र को वास्तव में सफल माना जाता है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का सार यही है कि सभी की भागीदारी से सभी की समृद्धि होती है।

इतना जटिल क्यों है भारत का भूमि बाजार

अराध्या सूद

बुरी तरह से संचालित भारतीय भूमि बाजारों की आर्थिक लागत क्या है? जमीन से संबंधित खबरें और सार्वजनिक नीतियां अक्सर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जैसे टाटा नैनो सिंगुर मामला या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम, 2013। भूमि बाजारों में गड़बड़ी या इससे जुड़े विवाद के कई कारण हैं। कई दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तरह भारत की जटिल विरासत प्रणाली के चलते भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं, और समय के साथ भूमि का विखंडन बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2015 में देश में कृषि योग्य भूमि की औसत जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर (2.7 एकड़) था, जो 1971 के 2.3 हेक्टेयर (5.7 एकड़) से कम था। छोटे-छोटे टुकड़ों के अलावा अस्पष्ट मालिकाना हक और सुस्त अदालतें देश में जमीन की खरीद को जोखिम भरा बना देती हैं। इसके अलावा, कृषि उपयोग वाली जमीन खरीदने में नौकरशाही और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भूमि विवाद भारतीय अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को प्रभावित करता है।

जैसे, बदतर तरीके से चालित भूमि बाजार भारतीय शहरों के आकार और विकास, आंतरिक प्रवास, बुनियादी ढांचे के विकास, पसंदीदा फसल, किसानों की आय, विनिर्माण उत्पादकता और विकास तथा अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक बदलाव को प्रभावित करते हैं। भारत में 68 फीसदी कृषि जोत को सीमांत खेत माना जाता है, जो एक हेक्टेयर से कम होता है। इसके विपरीत पाकिस्तान और अमेरिका में क्रमश: 36 फीसदी और शून्य फीसदी सीमांत खेत हैं।

नीतियों एवं विनियंत्रण के कारण छोटे भूखंड चकबंदी को कठिन बनाते हैं और कृषि उत्पादकता को नुकसान पहुंचाते हैं। शोध से पता चला है कि स्वतंत्रता के बाद सख्त बंटाई कानूनों के चलते बंटाईदारी घट गई, जिससे कृषि उत्पादकता में औसतन 38 प्रतिशत की कमी आई है। इसका एक और नतीजा यह है कि सीमांत खेतों में पर्याप्त मशीनों का उपयोग नहीं हो सकता, न ही नकदी फसलों की खेती हो सकती है। यानी ऐसे खेतों से ज्यादा लाभ नहीं उठाया जा सकता।

भारत में दो फीसदी विनिर्माण कंपनियों के पास दस या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, जबकि मैक्सिको और अमेरिका में ऐसी कंपनियों की संख्या क्रमश: आठ और चालीस फीसदी है। यह बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी कंपनियां कम शिक्षित श्रमिकों के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करती हैं। बड़ी भारतीय कंपनियां (दस या ज्यादा कर्मचारियों वाले) 35 फीसदी विनिर्माण श्रमिकों को रोजगार देती हैं, जबकि मैक्सिको में ऐसी कंपनियां 78 फीसदी विनिर्माण श्रमिकों को रोजगार देती हैं।

भारत में विनिर्माण कंपनियों के विकास न करने का एक कारण भूमि विवाद भी है। यदि कोई कंपनी अपना विस्तार करना या एक नई फैक्टरी लगाना चाहती है, तो उसे जरूरी भूमि अधिग्रहण के लिए सौ से ज्यादा भूस्वामियों से बात करनी पड़ती है। ऐसा परिवहन उपकरण और रसायन निर्माण जैसे उद्योगों के मामले में खासकर होता है। अमेरिका और भारत में ऑटोमोबाइल संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के उदाहरण से इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

इंडियाना में अपने फोर्ट वायने ऑटो संयंत्र के लिए कंपनी के महानिदेशक ने 29 भूस्वामियों से 379 हेक्टेयर भूमि दो महीने में खरीद ली। जबकि टाटा नैनो संयंत्र मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने 12,000 भूस्वामियों से 13,970 से अधिक भूखंडों को मिलाकर 404 हेक्टेयर भूमि एकत्र की थी। मैंने अपने शोध में पाया कि भूमि विवाद के चलते विनिर्माण कंपनियां टुकड़ों में भूमि अधिगृहीत करती हैं, और कई बार जमीन हासिल करने के लिए वर्षों इंतजार करती हैं।

सरकारी कंपनियों की तुलना में निजी कंपनियां छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन खरीदती हैं। इसके अलावा कंपनियों को जमीन की कीमत से ज्यादा खर्च पर्याप्त भूखंड एकत्र करने में करना पड़ता है। भूमि एकत्रीकरण की लागत दो रूपों में आती है-निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत। अपने यहां भूमि एकत्रीकरण के मामले में परिवर्तनीय लागत निश्चित लागत से ज्यादा मायने रखती है। प्रति हेक्टेयर परिवर्तनीय भूमि एकत्रीकरण लागत भूमि के आकार के साथ बढ़ती है।

इसलिए बड़ी कंपनियों के लिए लागत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा भूखंडों के छोटे आकार एवं अस्पष्ट मालिकाना हक के कारण होता है। निजी कंपनियों को सरकारी कंपनियों की तुलना में तीन गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। कई राज्यों में कंपनियां भूमि के लिए विक्रय मूल्य से दो गुना ज्यादा भूमि एकत्रीकरण के लिए भुगतान करती हैं। हमें समझना चाहिए कि सीमांत कृषि भूमि पर खेती आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और लाखों परिवारों के लिए आय का एकमात्र स्रोत है, भले ही उसका उत्पादक रूप से उपयोग न किया गया हो।

भले ही हम केवल सीमांत किसानों के लाभ को अधिकतम करने की परवाह करते हों, पर ऐसा कोई कारण नहीं है कि कृषि क्षेत्र में भूमि समेकन नीतियां आज भारत में अवैध हैं। भूमि एकत्रीकरण टकराव को देखते हुए भारत में बाजार समाधान कामयाब नहीं होने वाला है, जिसमें बिचौलिए सौदेबाजी करते हैं और जब तक अधिकतम लाभ नहीं मिलता, जमीन को खरीदते- बेचते रहते हैं। ऐसे में हमारे पास दो संभावनाएं बचती हैं।

पहली संभावना लैंड पूलिंग नीतियां हैं, जो कई राज्य सरकारें वर्तमान में विभिन्न पैमानों पर कर रही हैं। लैंड पूलिंग निश्चय ही विनिर्माण कंपनियों की कुल लागत कम करेगी और उनकी विकास दर में वृद्धि करेगी। दूसरी संभावना सरकारी एवं निजी कंपनियों के लिए भूमि एकत्रीकरण लागत कम करने की है। इसके लिए सरकार ने जमीन के पुराने दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। 30.2 करोड़ पंजीकरण रिकॉर्ड (आरओआर) में से 94 फीसदी पहले ही डिजिटाइज हो चुके हैं।

इसके अलावा, 13.5 प्रतिशत गांव के नक्शों का पुन: सर्वेक्षण किया गया है, हालांकि ये नक्शे आरओआर या विभिन्न राज्यों की अदालती व्यवस्था से जुड़े हैं या नहीं, यह पता नहीं है। एक बार डिजिटलीकरण और पुनर्सर्वेक्षण की इन मूलभूत बाधाओं को दूर करने के बाद भी भूमि का विखंडन कुछ हद तक भूमि एकत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा।

समरकंद में भारत

उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं। आने वाले दिनों में इस सम्मेलन की गूंज वैश्विक कूटनीति में महसूस हो सकती है। एक ही सम्मेलन में हमलावर रूस, साम्राज्यवादी चीन, अडिग ईरान, विशाल उभरते भारत और दर-दर मदद मांगते पाकिस्तान की मौजूदगी पर बहुत से देशों की नजर होगी। विशेष रूप से अमेरिका और नाटो के देशों की इस पर पैनी निगाह होगी। दूसरी ओर, एक हद तक अलग-थलग पडे. पुतिन इन दिनों विश्व स्तर पर मंच खोज रहे हैं, जो उन्हें शंघाई सहयोग संगठन से बेहतर कहीं और नहीं मिल सकता। वह अवश्य दर्शाना चाहेंगे कि चीन और भारत जैसे विशालकाय देश उनके साथ खड़े हैं। लगभग 18 देशों के इस सहयोग संगठन को अपने खेलों का आयोजन करने की सलाह देकर पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है कि इस संगठन का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। क्या आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर ये देश सोचने लगे हैं? क्या इन देशों में आर्थिक सहयोग को लेकर कोई शिकायत नहीं रही? सच यह कि किसी भी अन्य प्रकार के सहयोग को विस्तार देने से पहले इस संगठन के देशों को ईमानदारी से आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना चाहिए।

बहरहाल, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40 प्रतिशत आबादी इन देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने इन देशों के बीच बेहतर आपूर्ति शृंखला बनाने की यथोचित पैरवी की है। हालांकि, यह काम बहुत कठिन है। पाकिस्तान जहां हमें सामरिक रूप से तनाव दे रहा है, वहीं चीन के निशाने पर हमारी समग्र अर्थव्यवस्था भी है। यही कारण है कि चीन नीति के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकना चाहता है। चीन पहले से दुनिया का मैन्युफेक्चरिंग हब है और भारत अब उभरने की घोषणा कर रहा है। भारत का बाजार एससीओ के देशों में फैले, तो भारत को लाभ है। पर सच्चाई यह है कि दर-दर मदद मांग रहा पाकिस्तान भी भारत के प्रति अनुकूल रवैया रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर सवाल यहीं आकर अटक जाता है कि भारत ऐसे संगठन से दिलोजान से कितना जुड़े, जिसके कुछ सदस्य देश आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षधर हैं? गौर कीजिए, चीन या पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने इन दोनों देशों के नेताओं से दूरी बरतते हुए अपना साफ संदेश दे दिया है। बंदूकें और बातचीत एक साथ कैसे चले? भारत यदि चीन को आतंकवाद का दर्द दे रहा होता, तो चीन के नेता क्या करते? अत: हैरत की बात नहीं कि समरकंद में मंच पर मोदी और जिनपिंग अगल-बगल ही खड़े दिखे, पर दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाए और न मुस्कराए। यह दूरी तो चीन को ही दूर करनी पड़ेगी। क्या रूस इसके लिए चीन को मनाएगा और चीन आगे बढ़कर पाकिस्तान को सही राह दिखाएगा? वैसे विश्व राजनय में ऐसी भावुक उम्मीदों का स्थान नहीं होता, ज्यादातर देश या कारगर संगठन आर्थिक स्वार्थ से ही संचालित होते हैं। भलाई इसी में है कि भारत भी अपने आर्थिक हित को सबसे ऊपर रखे और आतंकवाद पर अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए दबाव बनाए रहे।

फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुवाई का समय शुरू है। इन फसलों की बुवाई मार्च तक चलती है। इस समय बोने पर ये फसलें अच्छी पैदावार देती हैं। इस मौसम में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पेठा, पालक, फूलगोभी, बैंगन, भिण्डी, अरबी जैसी सब्ज़ियों की बुवाई करनी चाहिए।

गर्मियों में उगाए सब्जियां होगा भरपूर फायदा

खीरा

खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुवाई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुवाई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई - गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें।

ककड़ी

ककड़ी की बुवाई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए एक एकड़ भूमि में एक किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की तीन से चार बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर दो - तीन बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें।

करेला

हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुवाई दो तरीके से की जाती है - बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की ज़मीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके बाद दो - तीन बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं।

लौकी

लौकी की खेती कर तरह की मिट्टी में हो जाती है लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांध कर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गरमी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं।

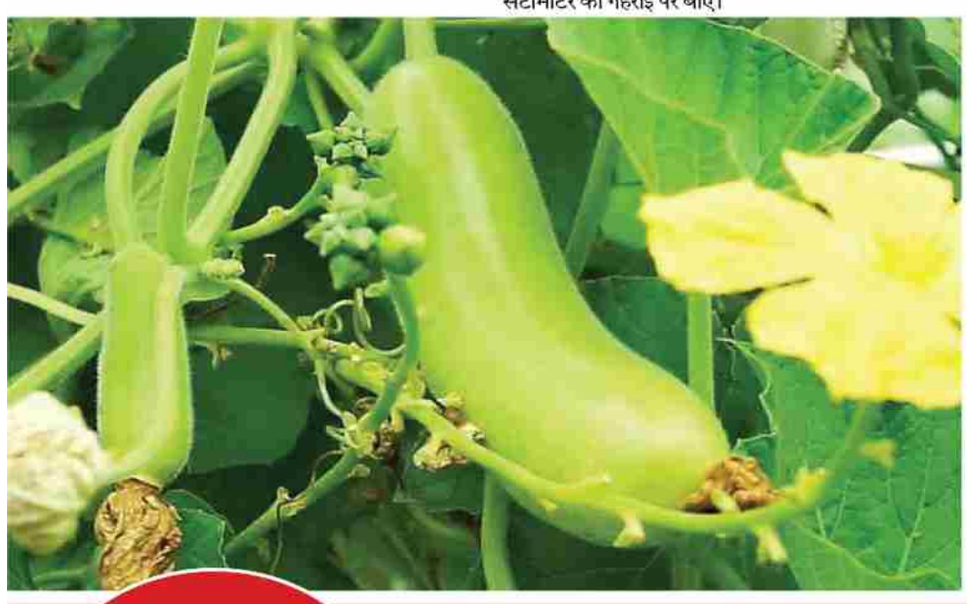

भिंडी

भिंडी की अगेती किस्म की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को दो-तीन बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सेमी और कतार में पौधे की बीच की दूरी 15-20 सेमी रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद पहली निराई-गुड़ाई करना जरुरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है।

तोरई

हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुवाई से पहले, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके बाद 2 से 3 बार बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत कि तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में न लगाएं इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। एक हेक्टेयर ज़मीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है।

अरबी

अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए ज़मीन गहरी होनी चाहिए। जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेमी. व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें।

पालक

पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है लेकिन ध्यान रहे अम्लीय ज़मीन में पालक की खेती नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब वह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना चाहिए, इसके बाद 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेन्टीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, इससे अधिक गहरी बुवाई नहीं करनी चाहिए।

बैंगन

इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुवाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर का खाद् बिखेर दे। बैंगन की खेती के लिए दो पौधों और दो कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए।

पेठा

पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सब से अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुवाई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर के मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर के पाटा लगाना चाहिए। इसके लिए एक हेक्टेयर में 7 से 8 किग्रा बीज की ज़रूरत होती है। इसकी बुवाई के लिए लगभग 15 हाथ लंबा का एक सीधा लकड़ी का डंडा ले लेते हैं, इस डंडे में दो-दो हाथ की दूरी पर फीता बांधकर निशान बना लेते हैं जिससे लाइन टेढ़ी न बने। दो हाथ की दूरी पर लम्बाई और चौड़ाई के अंतर पर गोबर की खाद का सीधे लाइन में गोबर की खाद घुरवा बनाते हैं जिसमे पेठे के सात से आठ बीजे गाड़ देते हैं अगर सभी जम गए तो बाद में तीन चार पौधे छोड़कर सब उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं।

बाढ़ के बाद दरिया जैसा दिखने लगा है पाकिस्तान, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई जरूरी : शरीफ

समरकंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं से कहा कि उनके देश में आई अभूतपूर्व बाढ़ के बाद यह दरिया जैसा दिख रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई। शरीफ उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एससीओ की राष्ट्र प्रमुख परिषद (सीएचएस) के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आने का उल्लेख किया। पाकिस्तान में बाढ़ में 1,500 से अधिक लोगों की मौत हो गयी और 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस साल 14 जून से आई भयावह बाढ़ में लगभग एक तिहाई पाकिस्तान डूब गया है। शरीफ ने कहा, ''पाकिस्तान में आई भयावह बाढ़ का कारण निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन, बादल फटने और अभूतपूर्व बारिश के साथ पहाड़ों से जलधाराएं मैदानों में आने की वजह से बाढ़ आई। इन सबके के कारण पाकिस्तान दरिया जैसा दिख रहा है।

जर्मनी ने रुसी कंपनी रोजनेफ्ट की अनुषंगी का नियंत्रण अपने हाथों में लिया

बर्लिन । जर्मन सरकार ने कहा कि वह रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की यहां स्थित अनुषंगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले रही है। सरकार ने कहा कि देश की तीन तेल रिफायनरी में परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि रोजनेफ्ट डॉयचलैंड, एरअएन रिफायनिंग एंड मार्केटिंग का नियंत्रण जर्मनी की संघीय नेटवर्क एजेंसी को सौंपा गया है। इसमें बताया गया कि एजेंसी तीन रिफायनरी- पीसीके शॉवेट, माइरो और बायेरनॉइल में कंपनियों के शेयर पर भी नियंत्रण रखेगी। मंत्रालय ने कहा कि जर्मनी की तेल शोधन क्षमता में 12 फीसदी हिस्सेदारी रोजनेफ्ट की है और इस कदम से निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उसने कहा कि यह व्यवस्था छह महीने के लिए की गई है।

अमेरिका में रेल श्रमिक संगठनों के साथ करार अंतिम चरण में, हड़ताल टली

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि श्रमिक संगठनों से मध्यम वर्ग बना है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि मध्यावधि चुनाव से पहले रेल कर्मचारियों की हड़ताल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। रेल कर्मचारियों की हड़ताल को टालने के प्रयासों के तहत उनके प्रशासन के अधिकारियों ने रेलवे और श्रमिक संगठनों के साथ वाशिंगटन में बातचीत जारी रखने के लिए पूरी कोशिश की। रात भर चली लंबी बातचीत के बाद सफलता मिली और बाइडेन ने घोषणा की कि हड़ताल टालने के लिए विभिन्न पक्ष एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं और इस पर श्रमिक संगठनों के सदस्य अंतिम फैसला करेंगे। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने हड़ताल को टालने के लिए हुए समझौते को सभी पक्षों की जीत बताते हुए एक बयान में इसकी सराहना की। उन्होंने कहा, इन रेल कर्मचारियों को बेहतर वेतन, बेहतर काम करने की स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को लेकर शांति मिलेगी- सभी कड़ी मेहनत से अर्जित हैं। यह समझौता रेलवे कंपनियों के लिए भी एक जीत है जो ऐसे उद्योग में अधिक कर्मियों को बनाए रखने और भर्ती करने में सक्षम होंगे जो आने वाले दशकों तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बने रहेगा। अगर रेलवे कर्मियों के 12 संगठनों के साथ समझौता नहीं होता तो शुक्रवार से रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती थीं और भोजन तथा ईंधन की ढुलाई ठप हो सकती थी। इससे प्रतिदिन दो अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता था।

पुतिन शरीफ से बोले- रूस पाकिस्तान को कर सकता है गैस की आपूर्ति

मास्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि उनका देश पाकिस्तान को गैस की आपूर्ति कर सकता है और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पहले से ही मौजूद है। पुतिन ने उज्बेकिस्तान में शंघाई शिखर सम्मेलन (एससीओ) से इतर शरीफ से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। रूस की एक सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा, मुद्दा रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन गैस की आपूर्ति का है, जो संभव है, जिसका अर्थ है कि बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा पहले ही तैयार किया जा जा चुका है, हमें अफगान मुद्दे को हल करना है। उन्होंने कहा ?कि निश्चित रूप से राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अफगान लोगों के साथ हमारे पारस्परिक अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का भी समाधान हो सकता है, मेरा मतलब देश की स्थिति पर पाकिस्तान के प्रभाव से है। शरीफ ने एससीओ बैठक से इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक की तथा परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान के साथ भी मुलाकात की और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी व बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री शरीफ के साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी समरकंद में हैं।

अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के पास खड़ा रॉयल गार्ड

लंदन । महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत को बुधवार को चार दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। उनकी अंत्येष्टि 19 सितंबर को की जाएगी। इस बीच इस हॉल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि महारानी के ताबूत के पास खड़ा एक गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। ज्ञात हो कि महारानी का पिछले गुरूवार को 96 साल की उम्र में बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया था। वह 70 साल से ब्रिटेन में शासन कर रही थीं। 12 सेकंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक प्लैटफॉर्म पर महारानी का ताबूत रखा है। चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं। इस दौरान महारानी के पार्थिव शरीर के पास खड़ा गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। काली यूनीफॉर्म पहने यह गार्ड मुंह के बल जमीन पर गिरा। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। इस दौरान कुछ देर के लिए इसका लाइव प्रसारण भी रोक दिया गया। महारानी का ताबूत जब लंदन के लिए एडिनबरा हवाई अड्डे से भेजा गया, तब वहां पर राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। महारानी के ताबूत के साथ उनकी बेटी प्रिंसेस एनी भी थीं जो रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ)के विमान से एडिनबरा से लंदन साथ आई हैं। महारानी के ताबूत को जिस विमान से लाया गया है, उसका इस्तेमाल पूर्व में मानवीय सहायता में किया जाता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत को स्कॉटलैंड के एडिनबरा से लंदन ले जाने वाले ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ट्रांसपोर्ट विमान पर करीब 60 लाख लोग नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे यह इतिहास में सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई है। महारानी का ताबूत मंगलवार शाम को आरएएफ ग्लोबमास्टर सी-17 विमान से एडिनबरा के सेंट गाइल्स चर्च से यहां लाया गया था।

रूसी सेना का अमानवीय कृत, यूक्रेन में फिर मिली 440 से अधिक शवों की सामूहिक कब्रे

कीव । रूस के यूक्रेन पर हमले को 6 महीने से भी अधिक समय के बाद भी घमासान जारी है और युद्ध के बीच जहां से रूसी सेना को भगाया है, वहां उनका अमानवीय कृत सामने आया है। यहां 440 से अधिक शवों की नई कब्र मिली है। यूक्रेन के पूर्वी शहर इजियम के बाहर एक जंगल में सामूहिक कब्र में इन शवों को दफन किया गया था। खार्किव इलाके के चीफ पुलिस इंवेस्टिगेटर सर्गेइ बोल्विनोव ने कहा कि हर एक शव की फोरेंसिक जांच की जाएगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इनमें से कुछ गोलाबारी और हवाई हमलों से मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अब तक मिले सबसे बड़े दफन स्थलों में से एक है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार रात टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा, 'खारकीव क्षेत्र के इजियम में एक सामूहिक कब्र मिली है। आवश्यक प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो गई हैं। इसे लेकर स्पष्ट सूचना कल मिल जानी चाहिए।' जेलेंस्की ने यूक्रेन के कुछ अन्य शहरों के नामों का भी जिक्र किया, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि वहां से पीछे हटी रूसी सेना सामूहिक कब्रें छोड़कर जा रही है और वहां युद्ध अपराधों के सबूत मिले हैं। राष्ट्रपति ने कहा, 'बुचा, मारियुपोल और अब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इजियम...रूसी सेना हर जगह मौत के निशान छोड़कर जा रही है और उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा। दुनिया को इस युद्ध की असल जिम्मेदारी रूस पर डालनी होगी।' मालूम हो कि रूसी सेना यूक्रेन की आक्रामक प्रतिक्रिया के बीच पिछले सप्ताह इजियम सहित खारकीव क्षेत्र के कई हिस्सों से पीछे हट गई थी। जेलेंस्की ने बुधवार को इजियम शहर का दौरा किया था।

समरकंद में शंघाई सहयोग सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और मंगोलियाई राष्ट्रपति उकहना खुरेलसुख।

भारतीय मूल के इम्तियाज अहमद फजल दक्षिण अफ्रीका के खुफिया महानिरीक्षक चुने गए

नई दिल्ली। भारतीय मूल के खुफिया सेवा अधिकारी इम्तियाज अहमद फजल को दक्षिण अफ्रीका की संसद ने देश के खुफिया महानिरीक्षक (आईजीआई) के पद पर नियुक्त किया है। आईजीआई को दक्षिण अफ्रीका की तीन मुख्य खुफिया सेवाओं-राज्य सुरक्षा एजेंसी, सैन्य खुफिया एजेंसी और दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवाओं के अपराध खुफिया विभाग में दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने की विधायी शक्ति हासिल है। नेशनल असेंबली ने खुफिया सेवा निगरानी अधिनियम-1994 की धारा 7(1) के अनुसार फजल के नामांकन को अनुमोदित किया। फजल ने 12 अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए आईजीआई पद के लिए अनुमोदन हासिल किया। इस पद के लिए कुल 25 आवेदन आए थे, जिनमें से 12 को साक्षात्कार के लिए चुना गया था। हालांकि, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा फजल की नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि किया जाना अभी बाकी है। नेशनल असेंबली की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 'अधिनियम के तहत संयुक्त स्थायी समिति (जेएससीआई) के लिए, एक दावेदार के नाम की सिफारिश पर नेशनल असेंबली के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य है।' बयान में कहा गया है, 'एक बार जब सदन जेएससीआई की सिफारिश को मंजूरी दे देती है तो संबंधित नाम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ताकि वह नामित व्यक्ति को आईजीआई के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकें।' दक्षिण अफ्रीका का आईजीआई पद 15 मार्च 2022 को सेतलोमोमारु आइजैक दिन्त्वे के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हो गया था।

एससीओ में नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती की दुहाई

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए भारत-अमेरिका की मित्रता के संबंध में हिंदी में तैयार एक नारे का अभ्यास करते नजर आए। रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन (आरएचसी) द्वारा जारी वीडियों में ट्रंप 'भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त' नारे का अभ्यास करते दिख रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप शिकागो के कारोबारी एवं आरएससी के सदस्य शलभ कुमार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। यह नया नारा ट्रंप के 2016 के 'अबकी बार ट्रंप सरकार' नारे से प्रेरित है।

इस नारे ने भारतीय अमेरिकियों का ध्यान आकर्षित किया था और कई प्रमुख प्रांतों में रिपब्लिकन पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 'अबकी बार ट्रंप सरकार' और 'भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त' के नारे तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले कुमार ने साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने और आरएचसी ने भारतीय-अमेरिकी समर्थन हासिल करने के लिए भारतीय मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति के नए नारे का प्रचार करने की योजना

बनाई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक और ताजा सर्वेक्षण इशारा करते हैं कि मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर बहुमत मिल सकता है। कुमार ने कहा, ''मुख्य मकसद सीनेट में पांच (रिपब्लिकन) उम्मीदवारों के लिए भारी समर्थन जुटाना है, जहां मतों का अंतर 50,000 से भी कम रहेगा और कुछ सीट पर तो यह 10,000 या पांच हजार मत के आसपास भी रह सकता है।''

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''हिंदू मतों से अंतर पड़ेगा। इनमें स्वतंत्र मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या है।'' कुमार और आरएचसी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों अलग हो गए थे। कुमार ने कहा कि उन्होंने इस साल 21 मार्च को मार-ए-लागो में ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद भी दोनों के बीच कुछ बैठकें हुई हैं। अमेरिका के पंजीकृत मतदाताओं में करीब एक प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी हैं।

अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद का किया ऐलान, 600 मिलियन डॉलर देगा

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

युद्ध की विभीषिका से गुजर रहे यूक्रेन को 6 महीने से अधिक हो गए हैं। युद्ध में अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। वॉशिंगटन ने एक बार फिर अतिरिक्त सैन्य सहायता में 600 मिलियन डॉलर के मदद की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी देते हुए कहा कि इस 600 मिलियन डॉलर पैकेज में अतिरिक्त हथियार, युद्ध सामग्री और उपकरण शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस 600 मिलियन डॉलर पैकेज के साथ यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता अब 15.8 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। विदेश सचिव ने आगे कहा कि मित्र राष्ट्रों और सहयोगी देशों के साथ अमेरिका इन हथियारों और उपकरणों को यूक्रेन को दे रहा है। इन हथियारों और उपकरणों का उपयोग यूक्रेन की सेना प्रभावी ढंग से कर रही है। इसके साथ ही सेना रूस के आक्रमण के खिलाफ अपने सफल जवाबी हमले को जारी रखे हुए है। ब्लिंकन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों का तब तक समर्थन करेगा जब तक उसे आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि सराहनीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ यूक्रेन के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 50 से अधिक देशों के साथ यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'हम जो क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के मैदान में अधिक अंतर लाने के लिए सावधानीपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। ब्लिंकन ने दोहराया कि अमेरिका सहयोगियों के साथ यूक्रेन के लिए मजबूती से खड़ा है। मालूम हो कि मास्को द्वारा यूक्रेन के अलग-अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में मान्यता देने के तीन दिन बाद रूसी सेना ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में हमला कर दिया था।' हमले के बाद यूके, यूएस, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा की और मास्को पर प्रतिबंध लगाए।

नेपाल का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत गोरखा भर्ती पर फैसला नवंबर में चुनाव के बाद होगा

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

नेपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय सेना में 'अग्निपथ योजना' के तहत गोरखा भर्ती के संबंध में फैसला 20 नवंबर को आम चुनाव के बाद नव-निर्वाचित सरकार करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लाम्साल ने काठमांडू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय सेना में अल्पकालिक भर्ती के संबंध में तत्काल फैसला लिए जाने की संभावना बेहद क्षीण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की यह टिप्पणी मीडिया में आयी उन खबरों पर प्रतिक्रिया है जिसमें भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडेय के हवाले से कहा गया है कि अगर नेपाल इस संबंध में जल्दी फैसला नहीं लेता है तो 'अग्निपथ योजना' के तहत मौजूदा भर्तियों में भारत को नेपाल से सैनिकों की भर्ती से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ेगा। जनरल पांडेय पिछले ही सप्ताह नेपाल यात्रा पर आए थे और अपने समकक्ष सहित हिमालयी देश के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। भारतीय सेना की अल्पकालीक भर्ती योजना 'अग्निपथ' के तहत गोरखा भर्ती 24 अगस्त से शुरू होनी थी। हालांकि, नेपाल के अनुरोध पर इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल 'नेपालखबर डॉट कॉम' की खबर के अनुसार, नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पर नेपाल फिलहाल भारतीय अधिकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 20 नवंबर को आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सरकार भारतीय सेना की 'अग्निपथ योजना' में गोरखा भर्ती पर फैसला लेगी।

पाकिस्तान को अव्यवस्था से बचाने का एकमात्र उपाय जल्द चुनाव कराना है: इमरान खान

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश को अव्यवस्था से बचाने का एकमात्र रास्ता जल्द और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना है। खान ने आगाह किया कि देश की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और ऐसे स्तर तक पहुंच सकती है, जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख ने एक वीडियो संबोधन में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि पिछले पांच महीने के दौरान उनका शासन निराश करने वाला रहा है।

उन्होंने कहा, 'मुल्क को अव्यवस्था में जाने से बचाने के

लिए जल्द और पारदर्शी चुनाव कराना ही एकमात्र रास्ता है.. अगर चुनाव नहीं हुए तो चीजें काबू से बाहर हो जाएंगी।' खान ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता से ही अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें देश को इस नाजुक हालात से बाहर निकालना है... वे (सरकार) तेजी से देश को अव्यवस्था की ओर धकेल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा सरकार के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि खान की अगुवाई पिछली सरकार ने ही स्थिति खराब की थी। उन्होंने दावा किया कि जब उनकी सरकार गिराई गई, उस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक थी। खान ने दावा किया कि दुनियाभर में मंहगाई समेत अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने ईंधन की कीमतों और बिजली की दरों में कटौती की।

उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में निर्यात 24 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर पहुंच गया और प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला धन भी 19 अरब डॉलर से बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गया था, जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिली। खान ने कहा कि उनकी सरकार 16 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार छोड़कर गई थी जो अब घट कर आठ अरब डॉलर रह गया है। खान ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप सहित अन्य झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

चीन ने ताइवान की रक्षा का समर्थन करने वाले अमेरिकी सीनेट विधेयक की कड़ी आलोचना की

बीजिंग (एजेंसी)।

अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति द्वारा ताइवान को रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अमेरिका पर 'वन-चाइना' के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा कि चीन ने संबंधित विधेयक को लेकर अमेरिका से 'गंभीर शिकायतें' दर्ज कराई हैं।

इस विधेयक के कानून में तब्दील होने के लिए अब भी अमेरिकी सदन और राष्ट्रपति जो बाइडन की मंजूरी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ''वन-चाइना सिद्धांत चीन-अमेरिका के संबंधों का राजनीतिक आधार है। अगर बिल पर विचार-बिमर्श जारी रहा, इसे मंजूरी दी गयी या इस पर हस्ताक्षर किया गया, तो यह चीन-अमेरिका की राजनीतिक नींव को हिलाकर रख देगा तथा ताइवान जलडमरूमध्य में दोनों देशों के बीच संबंधों तथा शांति और स्थिरता की दृष्टि से गंभीर परिणाम होंगे।''

बुधवार को समिति द्वारा अनुमोदित ताइवान नीति अधिनियम 2022, ताइवान की 'सुरक्षा और उसके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन' को मंजूरी देता है और इसके तहत अमेरिका, ताइवान की जवाबी हस्तक्षेप क्षमताओं को बढ़ाने में रक्षा फंड के तहत अरबों डॉलर प्रदान करेगा। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ विधेयक तैयार करने वाले अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा, ''आज हम जिस विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं, वह स्पष्ट करता है कि अमेरिका, चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता है या तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है।

इसके ठीक विपरीत हम सावधानीपूर्वक तथा रणनीतिक दृष्टि से ताइवान के ऊपर अस्तित्व के खतरे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।'' विधेयक को समिति की मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब पिछले महीने अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही अधिक था।

इस घटना ने चीन को ताइवान जलडमरूमध्य में मिसाइलें दागने और द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास के नाम पर बड़ी संख्या में जहाजों और युद्धक विमानों को जुटाने के लिए उकसाया। एक बयान में, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह विधेयक पर ''इस उम्मीद के साथ अमेरिकी सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखेगाकि यह कानून में तब्दील हो सकता है, जिससे अमेरिका और ताइवान के बीच दोस्ताना संबंध आगे बढ़ सकते हैं तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जडेजा का विकल्प तलाशेगी भारतीय टीम

मुबई (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्वकप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा का विकल्प तलाशने का प्रयास करेगी। जडेजा एशिया कप में चोटिल होने के बाद से ही टी20 विश्वकप से भी बाहर हो गये हैं क्योंकि उनकी सर्जरी हुई है। ऐसे में उनके विकल्प के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जडेजा स्पिनर होने के साथ भी एक आक्रामक बल्लेबाज ओर बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी हैं। ऐसे में उनका बाहर होना टीम के लिए करार झटका है। जडेजा ने पिछले कुछ समय में जरुरत पड़ने पर बड़ी पारियां खेली हैं। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी के लिए उनकी कमी पूरी करना आसान नहीं रहेगा।

अक्षर के अलावा भी कई खिलाड़ी हैं, जिन्हें जडेजा के विकल्प के तौर पर टी20 विश्व कप के दल में रखा गया है। अब इनमें से कौन सा खिलाड़ी, टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के अंतिम ग्यारह का हिस्सा बनता है। इसका पता ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू टी20 सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

जडेजा इसलिए भारतीय टीम के लिए अहम हैं क्योंकि वह अपनी गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी और फील्डिंग से भी किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

जडेजा ने सितंबर 2020 से अब तक गल दो साल में 15 टी20 में 56.80 की औसत से 284 रन बनाए हैं। इसमें उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से ऊपर का है। इस अवधि में जडेजा ने चार बार 30 से अधिक रन बनाये हैं। इसमें से तीन अवसरों पर वह नाबाद रहे हैं। इस प्रकार टीम के लिए मैच फिनिशर भी रहे हैं। इसी अवधि में जडेजा ने 15 मैच में 6.84 की इकोनॉमी रेट से 12 विकेट लिए हैं। ऐसे में उनका न होने से गेंदबाजी पर भी असर पड़ेगा।

अक्षर को जडेजा के चोटिल होने के कारण ही टी20 विश्व कप के स्क्वॉड में शामिल किया गया है। वो भी जडेजा की तरह ही स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अक्षर भी नंबर-7 पर उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि, वो जडेजा की तरह ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं, जिन्हें शीर्ष क्रम पर भेजा जा सकता हो। वह निचले क्रम पर ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें अंतिम ग्यारह में मौका दिया जाता है, तो इससे गेंदबाजी तो मजबूत हो जाएगी। कम से कम छठे गेंदबाज के रूप में एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा पर बल्लेबाजी में गहराई नहीं रहेगी। अक्षर ने इस साल 11 टी20 खेले हैं और इसमें से 5 में बल्लेबाजी नहीं की। उनका सबसे अधिक स्कोर नाबाद 20 रन है। जो बेहद सामान्य है।

वहीं दीपक हुडा को भी टी20 विश्व कप के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। हुडा भी नंबर-7 पर भारत के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वो बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। हुडा को अगर अंतिम ग्यारह में शामिल किया जाता है, तो उससे बल्लेबाजी तो जरूर मजबूत होगी पर गेंदबाज नहीं। ऐसे में हार्दिक पंड्या पर अपने कोटे के 4 ओवर डालने का दबाव आ जाएगा।

इसी को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हुडा को अवसर दे सकता है। इससे टी20 विश्व कप से पहले यह साफ हो जाएगा कि वह जडेजा की जगह ले सकते हैं या नहीं।

वहीं दिग्गज स्पिनर आर अश्विन भी जडेजा के विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने आईपीएल-2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी की थी। बीते एक साल में उन्होंने टी20 के लिहाज से अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया में

खेलने का अनुभव है और वो टी20 में पावरप्ले के साथ ही बीच के ओवर में भी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं।

अमरीका ने डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में जगह लगभग पक्की की

ग्लासगो (एजेंसी)।

टॉमी पॉल और टेलर फ्रिट्ज ने अपने एकल मैचों में विपरीत अंदाज में जीत दर्ज की जिससे अमरीका ने कजाखस्तान को 2-1 से हराकर डेविस कप फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर दी।

अमरीका ग्रुप डी में दो मैच जीतकर शीर्ष पर है और उसका अंतिम आठ में पहुंचना लगभग तय है। पॉल ने मिखाइल कुकुश्किन पर 6-1, 6-4 से आसान जीत दर्ज की। इससे पहले फ्रिट्ज ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को तीन सेट में 7-6 (6) 1-6 6-3 से हराया था। बुब्लिक और अलेक्सांद्र नेदोवियसोव ने बाद में युगल मैच में राजीव राम और जैक सॉक को 6-2, 7-6 (6) से पराजित किया।

जर्मनी के हैम्बर्ग में खेले गए ग्रुप सी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती हार से उबरकर फ्रांस को 2-1 से हराया। रिचर्ड गास्केट ने जेसन कुबलर पर 6-2, 6-4 से हराकर फ्रांस को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन एलेक्स डी मिनौर ने बेंजामिन बोन्ज़ी पर 6-3, 1-6, 6-4 से जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर ला दिया।

इसके बाद मैथ्यू एबडेन और मैक्स पुरसेल ने निकोलस माहुत और आर्थर रिंडरकनेच को 6-4, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया दो जीत से ग्रुप में शीर्ष पर है। अन्य मुकाबलों में सर्बिया ने ग्रुप बी में कोरिया को 2-1 से और क्रोएशिया ने ग्रुप ए में स्वीडन को 2-1 से हराया।

संजू सैमसन करेंगे इंडिया-ए की कप्तानी, राज बावा को भी मिली टीम में जगह

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

युवा हरफनमौला खिलाड़ी राज अंगद बावा को 22 सितंबर से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला के लिए संजू सैमसन की अगुवाई वाली भारत ए टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला के अगले दो मैच 25 और 27 सितंबर को खेले जायेंगे। तीनों मैचों की मेजबानी चेन्नई करेगा। दलीप ट्रॉफी में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया है जिसमें भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे पर गये ज्यादातर खिलाड़ी शामिल है। भारत को अंडर-19 विश्व कप चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बावा मध्यम गति के तेज गेंदबाज और बायें हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के लिए सिर्फ दो रणजी मैच खेले है लेकिन समझा जाता है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति हार्दिक पंड्या के लिए विकल्प तैयार करना चाहती है। पंड्या को चोटिल होने से बचाने के लिए उनके कार्यभार प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ रहा है। शिवम दुबे और विजय शंकर जैसे हरफनमौला को इस बीच आजमाया गया लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर खुद पर को साबित करने में विफल रहे। ऐसे में चयनकर्ता तेज गेंदबाजी हरफनमौला खिलाड़ियों का एक पूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पास स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के कई विकल्प हैं, लेकिन निचले मध्य क्रम वाले अच्छी बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी करने वालों की संख्या काफी कम है। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ श्रृंखला में चयनकर्ताओं को बावा की क्षमता का आकलन करने का मौका मिलेगा।

भारत ए टीम: पृथ्वी साव, अभिमन्यु ईश्वरन, रुतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, संजू सैमसन (कप्तान), केएस भरत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, शाहबाज अहमद, राहुल चाहर, तिलक वर्मा, कुलदीप सेन, शारदुल ठाकुर, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, राज अंगद बावा।

वीरेंद्र सहवाग बनाम कैलिस 'चैरिटी' मैच से होगा लीजेंड्स लीग क्रिकेट का आगाज

बैंगलुरु (एजेंसी)।

कोलकाता। वीरेंद्र सहवाग और 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल उन 90 पूर्व क्रिकेटरों में शामिल है, जो शुक्रवार को यहां 'चैरिटी' मैच के साथ ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले 'लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी)' में हिस्सा लेंगे। सहवाग गुजरात जायंट्स टीम की अगुवाई करेंगे जो शनिवार को लीग के शुरुआती मैच में गौतम गंभीर की इंडिया कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इससे पहले हालांकि शुक्रवार को वह एक 'चैरिटी' मैच में इंडियन महाराज टीम की कप्तानी करेंगे जिसका सामना दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस की अगुवाई वाली टीम वर्ल्ड जायंट्स से होगा।

इस मैच का मकसद पूर्व दिग्गज कपिल देव की एनजीओ खुशी फाउंडेशन के लिए रकम जुटाना है। खुशी फाउंडेशन लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। चार टीमों के टूर्नामेंट में हरभजन सिंह मणिपाल टाइगर्स की कप्तानी करेंगे जबकि इरफान पठान भीलवाड़ा किंग्स का नेतृत्व करेंगे। लीग में सभी अंपायर महिलाएं होंगी। टूर्नामेंट का पहला सत्र इस साल की शुरुआत में मस्कट में आयोजित किया गया था।

विटोरी ने कहा, टी20 विश्व कप में आस्ट्रेलियाई विकेट पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे अश्विन

मुंबई। (एजेंसी)।

न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी को लगता है कि आर अश्विन की परिस्थितियों से तेजी से सामंजस्य बैठाने की काबिलियत और आस्ट्रेलियाई परिस्थितियों की अपार जानकारी उन्हें टी20 विश्व कप के दौरान मदद करेगी। आस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों की बात आती है तो स्पिन गेंदबाज इतने प्रभावी नहीं होते और भारत के पास अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिये अश्विन, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान विटोरी यहां लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे चरण में खेलने के लिये यहां आये हुए हैं। उन्होंने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि अश्विन टेस्ट में शानदार रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं और उन्हें भारत के लिये टी20 टीम में शामिल किया गया है।'' उन्होंने कहा, ''वह उन खिलाड़ियों में शामिल है जो बहुत जल्दी परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाते हैं, वह समझते हैं कि उन्हें सभी परिस्थितियों में क्या करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर उसे चुना जाता है तो वह जानता है कि प्रदर्शन किस तरह करना है। वह कई बार आस्ट्रेलियाई दौरों पर जा चुके हैं।'' विटोरी ने कहा कि रविंद्र जडेजा चोटिल हैं तो अश्विन को आगामी टी20 विश्व कप में स्पिन गेंदबाजी आल राउंडर स्थान पर रखा जा सकता है।

हालेप की नाक की सर्जरी हुई

वॉशिंगटन। रोमानियाई टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप के नाक की सर्जरी हुई है। इस सर्जरी कारण अब हालेप इस साल के अंत तक खेल से दर रहेगी। हालेप को सांस लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए ही उसकी यह सर्जरी करायी गयी है। इस खिलाड़ी ने ट्विटर पर अपने सर्जरी के सफल होने की जानकारी दी है। .

इस रोमानियाई स्टार ने कहा, ''मैं कुछ समय से नाक की समस्याओं से जूझ रही थी। गर्मियों के दौरान मेरी स्थिति और खराब हो गई थी। इस समस्या ने मेरे लिए सांस लेना कठिन बना दिया। रात में मुझे और भी दिक्कतें आने लगीं। ऐसे में समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका सर्जरी ही था।' हालेप ने कहा, 'मेरा 2022 का सत्र समाप्त हो गया है। यह मेरे लिए एक शानदार वर्ष रहा है। अब 2023 में कोर्ट पर मुलाकात होगी। मुझे लगता है अभी भी टेनिस कोर्ट पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूं और मेरा वही लक्ष्य हैं। वैसे 30 साल की हालेप ने स्वीकार किया कि वह फरवरी में खेल से संन्यास लेने के बारे में सोच रही थीं। गौरतलब है कि विश्व की पूर्व नंबर-1 खिलाड़ी सिमोना हालेप की इससे पहले भी सर्जरी हुई थी।

17 साल के बाद पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम करेगी बाढ़ पीड़ितों की सहायता

कराची। 17 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भीषण बाढ़ पर चिन्ता जताते हुए पीड़ियों की सहायता की घोषणा की है। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर के अनुसार 7 मैचों की इस टी20 सीरीज से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो बाढ़ के कारण निराश में जी रहे हैं। देश में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों को खों लोगों के उत्साह को बढ़ाने में कारगर होगी। इंग्लैंड टीम को अगले सप्ताह से सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की इस सीरीज से अगले माह ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी20 विश्व कप की तैयारियों में सहायता मिलने की उम्मीद है।

बटलर ने कहा की अभी पाक के लोगों का मुश्किल समय चल रहा है। वहीं हम भी एक टीम के रूप में उनकी सहायता करना चाहते हैं। खिलाड़ियों के साथ ही इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) भी लोगों की सहायता करेगी। यह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास भर है हालांकि इसके अलावा लोगों को अन्य जगहों से भी सहायता की जरुरत है। उम्मीद है कि हम इस दौरे में रोमांचक क्रिकेट खेल कर लोगों का हौंसला बढ़ाने में सफल रहेंगे।' गौरतलब है कि बटलर सहित इंग्लैंड के ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार पाक का दौरा कर रहे हैं। टीम में वापसी करने वाले एलेक्स हेल्स, मोइन अली और लियाम डॉसन ने पाक सुपर लीग में भी हिस्सा लिया था।

मार्क बाउचर मुंबई इंडियन्स के मुख्य कोच नियुक्त, माहेला जयवर्धने की लेंगे जगह

मुंबई। (एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के लिए मुंबई इंडियंस का कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को यह घोषणा की। यह 45 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर श्रीलंका के पूर्व कप्तान माहेला जयवर्धने का स्थान लेंगे जिन्हें फ्रेंचाइजी ने हाल में अपना वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया था। बाउचर दक्षिण अफ्रीका की पुरुष राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच हैं। उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में घोषणा की थी कि वह आगामी टी-20 विश्वकप के बाद अपना पद छोड़ देंगे।

बाउचर ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा,'' मुंबई

इंडियंस का मुख्य कोच नियुक्त किया जाना सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुंबई इंडियंस का इतिहास और उपलब्धियां उसे खेल जगत की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल करते हैं। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं।'' दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपरों में से एक बाउचर के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शिकार का रिकॉर्ड दर्ज है। बाउचर संन्यास लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष स्तर की क्रिकेट फ्रेंचाइजी टाइटंस के कोच बने थे। उनके रहते हुए टाइटंस ने पांच घरेलू खिताब जीते।

उन्हें 2019 में दक्षिण अफ्रीका का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था जहां उनके नाम पर टेस्ट मैचों में 11, वनडे में 12 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 23 जीत दर्ज हैं। रिलायंस जिओ के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा,'' मुंबई इंडियंस में मार्क बाउचर का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। मैदान के अंदर और बाहर उन्होंने अपनी विशेषज्ञता साबित की है और उम्मीद है कि वह मुंबई इंडियंस की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे।

मुरलीधरन ने टी20 विश्व कप में हरसंगा से सावधान रहने की दी सलाह

नई दिल्ली (एजेंसी)।

श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन अगले महीने होने वाले टी 20 विश्व कप से पहले टीमों को आगाह करते कहा कि उन्हें वानिंदु हसरंगा के खिलाफ सावधान रहना होगा क्योंकि यह अबूझ स्पिनर ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर खतरनाक होगा। हसरंगा ने हाल ही संपन्न एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में नौ विकेट झटक कर अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मुरलीधरन ने कहा कि टी20 विश्व कप में हसरंगा के प्रदर्शन पर नजरें होंगी। मुरलीधरन ने 'लीजेंड्स लीग क्रिकेट' के दूसरे सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, 'वह टी20 प्रारूप का शानदार गेंदबाज है। पिछले दो-तीन वर्षों में उसने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है।'' टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया की परिस्थियों में अंगुली के स्पिनरों की तुलना में लेग स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है। वह बल्लेबाजों के लिए मुश्किल चुनौती पेश करेगा। बल्लेबाजों को उसके खिलाफ सतर्क रहना होगा। उन्होंने एशिया कप में टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, '' पिछले कुछ वर्षों से हमारी टीम काफी युवा है। एशिया कप में हमने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेला। वे इस दौरान सर्वश्रेष्ठ टीम लगे और एशिया कप में जीत के हकदार थे।''

मुरलीधरन इस मौके पर दिवंगत महान गेंदबाज शेन वार्न को याद कर भावुक हो गये। उन्होंने वार्न को खुद बेहतर बताते हुए कहा, '' मुझे लगता है कि वह मुझसे बेहतर थे, जब मैं खेल रहा था तो मैं उनसे प्रेरणा लेता था। हम सब उन्हें याद करते हैं।'' मुरलीधरन लीजेंड्स लीग क्रिकेट में मणिपाल टाइगर्स टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

किपलिमो दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लेंगे

नई दिल्ली। अगले माह 16 अक्टूबर को यहां होने वाली दिल्ली हाफ मैराथन में युगांडा के विश्व रिकॉर्डधारी जैकब किपलिमो भी भाग लेंगे। आयोजकों ने कहा कि किपलिमो के आने से इस रेस का आकर्षण बढ़ेगा। किपलिमो इससे पहले साल 2020 में खिताब जीतकर विश्व हाफ मैराथन चैम्पियन बने थे। उन्होंने लिस्बन में 57:31 मिनट के विश्व रिकॉर्ड के साथ यह दौड़ पूरी की।

इस खिलाड़ी का यह सत्र शानदार रहा है जिसमें उन्होंने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 57:56 का समय निकालकर आरएके हाफ मैराथन और फिर 'ग्रेट नॉर्थ रन' हाफ मैराथन 57:56 का समय निकाल कर जीती। किपलिमो ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा का कांस्य पदक भी जीता था। उन्होंने पिछले माहराष्ट्रमंडल खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में दो स्वर्ण पदक भी हासिल किये थे।

बुमराह ने टी20 विश्वकप के लिए तैयारियां शुरु कीं

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अगले माह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं। बुमराह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बुमराह इससे पहले चोटिल होने के कारण एशिया कप 2022 में नहीं खेल पाए थे। एशिया कप में भारतीय टीम को उनकी कमी महसूस हुई थी। बुमराह विश्वकप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से टीम में वापसी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 20 सितंबर से शुरु होगी। बुमराह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, ' कड़ी मेहनत करें और आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं. बीसीसीआई ने हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा की है जिसमें बुमराह वापसी करने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप से पहले बुमराह के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलना लाभदायक साबित हो सकता है। इससे उन्हें लय में आने का पूरा अवसर मिलेगा। उनकी वापसी से टीम इंडिया का गेंदबाजी आक्रमण बेहतर होगा।

फिक्सिंग के संदेह में पाक के दो क्रिकेटर

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के मामले में स्पिनर आसिफ अफरीदी के खेलने पर रोक लगायी है। अब उसके दो और क्रिकेटर भी संदेह के घेरे में हैं। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं अभी तक यह नहीं पता चला है। अगर ये दोषी पाये गये तो बोर्ड इनपर भी प्रतिबंध लगायेगा। पीसीबी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के कुछ अधिकारियों को इस मामले की गहन जांच के लिए मुजफराबाद भेजा गया है। अफरीदी बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उन्होंने हाल ही में नेशनल टी20 कप में भाग लिया था। पीसीबी ने अपने एक अन्य बयान में लिखा, 'आसिफ को आज पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 के तहत दो नियमें के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्हें आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन की राहत दी गई है।' बोर्ड ने कहा कि उनके खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए पीसीबी परिणाम आने तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

भारतीय महिला टीम को मिली करारी शिकस्त, इंग्लैंड ने टी20 सीरीज जीती

ब्रिस्टल। (एजेंसी)।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारतीय महिला टीम को गुरुवार को यहां इंग्लैंड से तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सात विकेट से करारी हार का सामना पड़ा। इंग्लैंड ने इस तरह से तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। उसने पहले टी20 मैच में नौ विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि भारत ने दूसरे मैच में आठ विकेट से जीत हासिल करके अच्छी वापसी की थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तीसरे और निर्णायक मैच में लय बरकरार रखने में नाकाम रहे और भारत पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने आठ विकेट पर 122 रन ही बना पाया।

इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। अब इन दोनों टीम के बीच रविवार से तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी। भारत टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा लेकिन जल्द ही उसका शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। भारत ने अपने चोटी के पांच बल्लेबाज केवल 35 रन पर गंवा दिए थे। इनमें सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (पांच), स्मृति मंधाना (नौ) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (पांच) के विकेट भी शामिल हैं। सुभिनेनी मेघना और डी हेमलता खाता भी नहीं खोल पाई जबकि स्नेह राणा (आठ) के आउट होने से स्कोर छह विकेट पर 52 रन हो गया।

भारतीय टीम यदि 100 रन के पार पहुंच पाई तो उसका श्रेय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को जाता है जिन्होंने 22 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 33 रन बनाए। ऋचा के अलावा दीप्ति शर्मा (24) और पूजा वस्त्राकर (नाबाद 19) ही दोहरे अंक में पहुंची। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 25 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि सारा ग्लेन ने तीन ओवर में 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए। छोटे लक्ष्य के सामने सोफिया डंकले (44 गेंदों पर 49) और डैनी वाइट (22) ने पहले विकेट के लिए 70

रन जोड़कर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद एलिस कैप्सी (24 गेंदों पर नाबाद 38) और ब्रायोनी स्मिथ (नाबाद 13) ने 10 गेंद शेष रहते ही इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा और राधा यादव ने एक-एक विकेट लिया।

गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को बताया आतंकी हमला, कहा- असली अपराधियों के नाम छिपा रहे नीतीश

बेगूसराय, 16 सितम्बर (नि. सं.)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को लेकर नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। गिरिराज ने शुक्रवार को कहा कि बेगूसराय गोलीकांड महज एक वारदात नहीं बल्कि आतंकी हमला था। सीएम नीतीश कुमार असली अपराधियों के नाम छुपाने में लगे हैं। इस केस की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जाए। बता दें कि इस मामले में बेगूसराय पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक समाचार चैनल से बातचीत में नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वे तथ्यों को छिपा रहे हैं। ये एक गोलीकांड नहीं बल्कि आतंकी हमला है। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य का मुखिया इस घटना की लीपापोती करने में जुटा है। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पर हमला है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को डूब कर मर जाना चाहिए। वे लोगों की बातों में आकर बयान दे रहे हैं, क्या उनके पास कोई सिस्टम नहीं है? इनका सिस्टम फेल कर गया था। जहां हमला हुआ वहां किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि हिंदू समाज के हर वर्ग के लोग थे, इसलिए ये आतंकी हमला है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार 2013 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पटना के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस वक्त भी एक ही वर्ग के लोगों ने हमला किया था। उन्होंने बेगूसराय गोलीकांड की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है।

सोनाली फोगाट की मौत की जांच के लिए गोवा पहुंची सीबीआई टीम

पणजी, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को गोवा पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोगाट की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फोगाट की बेटी और हरियाणा के लोगों की मांग पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया है।

सावंत ने कहा, 'मुझे गोवा पुलिस पर भरोसा है। वे अच्छे तरीके से जांच कर रही है और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन लोगों और उनकी बेटी की मांग को देखते हुए मैंने सीबीआई जांच के लिए मामले की सिफारिश की।'

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि सीबीआई की टीम अंजुना के उस होटल का दौरा करेगी, जहां फोगाट उस रात रुकीं थीं।

फोगाट 22 अगस्त को गोवा के एक होटल में थीं। उस रात बेचैनी महसूस करने वाली फोगाट को अगली सुबह सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने 26 अगस्त को सुधीर सांगवान (फोगाट के पीए) को सुकविंदर सिंह के साथ उनकी हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा कि फोगाट को कथित तौर पर मेथेम्फेटामाइन ड्रग्स दी गई थी, जब वह अंजुना में कर्लीज होटल में पार्टी कर रही थी। इस मामले में रेस्टोरेंट के सह मालिक एडविन नून्स और दो ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था। गोवा में विपक्षी दलों ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

भारत 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का कर रहा है सामना : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत बीते 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है और देश के युवाओं के भविष्य को मजबूती प्रदान करना व उनके मन में सकारात्मकता लाना उनकी पार्टी का कर्तव्य है। गांधी सात सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा' के सिलसिले में आज कोल्लम जिले के नीन्दकारा पहुंचे हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में गांधी ने लिखा कि वह इस यात्रा के दौरान अनेक युवाओं से मिल रहे हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश युवा शक्ति का उपयोग करे, तो बहुत तेजी से विकास कर सकता है।

गांधी ने कहा, लेकिन देश में पिछले 45 वर्षों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और निराश हैं। यह हमारा कर्तव्य है और आज समय की मांग भी है कि हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूती प्रदान करें, उनमें सकारात्मकता लाएं। भारत जोड़ो यात्रा' के सुबह के चरण के समापन के बाद, गांधी काजू उत्पादकों, उद्यमियों, ट्रेड यूनियनों और कांग्रेस पार्टी के दो सहयोगी दलों आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चाएं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं अनेक युवाओं से मिल रहा हूं, सरकार से उनकी उम्मीदों को समझ रहा हूं कि वे अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं तथा हम उनके लिए और कितनी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। गांधी ने यह भी कहा कि यात्रा का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों और आदिवासियों की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा हमसे खुलकर बात कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सभी अपने भारत को एकजुट करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। यात्रा का शाम का चरण चावरा बस स्टैंड से शुरू होगा और करुणागपल्ली में समाप्त होगा जहां भारत जोड़ो यात्रा'' के सदस्य रात भर रुकेंगे। कांग्रेस का 3,570 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ और जम्मू-कश्मीर में समाप्त होगा। दस सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा एक अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। इससे पहले 19 दिन तक केरल के सात जिलों में 450 किलोमीटर की यात्री की जाएगी।

एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर लगाया 3000 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनल (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है। बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेली भी शामिल थे।

बेंच ने कहा, चूंकि, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पहले के आदेशों के तहत जल प्रदूषण की रोकथाम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दी गई समयसीमा समाप्त हो गई है, इसलिए 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत को एक जनवरी 2021 से लागू किया जाना है और पर्यावरण को हुए नुकसान व प्रबंधन की लागत के बराबर मुआवजा लगाया जाना है।

बेंच ने कहा कि भविष्य में लगातार जारी क्षति को रोकने और पिछले नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। एनजीटी ने 1,250 मिलीलटर प्रति दिन (एमएलडी) तरल अपशिष्ट या सीवेज के निस्तारण में कमी के लिए मुआवजे का निर्धारण 2,500 करोड़ रुपये के रूप में किया।

बेंच ने कहा कि वैज्ञानिक रूप से ठोस कचरे का प्रबंधन करने में विफलता के मद में कुल मुआवजा 555 करोड़ रुपये है। उसने कहा कि कुल मुआवजा 3,000 करोड़ रुपये पूर्णांकित किया गया है, जो राजस्थान सरकार द्वारा दो महीने के भीतर एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है, जिसका संचालन मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार किया जाएगा और जिसका इस्तेमाल नुकसान की भरपाई के उपायों पर होगा।

बेंच ने कहा कि सीवेज प्रबंधन के संबंध में नुकसान की भरपाई के उपायों में सीवेज निस्तारण और उपयोग प्रणाली स्थापित करना तथा मौजूदा सीवेज प्रबंधन प्रणालियों व उनकी संचालन व्यवस्था का उन्नयन करना शामिल है, ताकि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

एनजीटी ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निष्पादन योजना में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के तहत जैव-उपचार प्रक्रिया के निष्पादन के साथ-साथ आवश्यक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना और 161 साइटों का उपाय करना शामिल होगा।

बेंच ने आगे कहा कि नुकसान की भरपाई से जुड़ी दोनों योजनाओं को समयबद्ध तरीके से राज्यभर में तुरंत क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त मुआवजा तय करने पर विचार किया जाएगा। बेंच ने कहा कि अनुपालन मुख्य सचिव के जिम्मे होगा। इसके अलावा, मुख्य सचिव द्वारा सत्यापन योग्य प्रगति पर छह मासिक प्रगति रिपोर्ट दायर की जाएंगी। रिपोर्ट की एक प्रति इस अधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल को भी सौंपी जाएगी।

गोवा में बीजेपी समर्थित मेयर उम्मीदवार की हार, घर में ही भद्द पिटे पूर्व सीएम दिगंबर कामत

पणजी, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को अपने घर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है।

दक्षिण गोवा में मडगांव नगर परिषद के मेयर पद के लिए उनके समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। मडगांव की सीट कामत का घरेलू मैदान माना जाता है। पिछले कई बार से कामत मडगांव की सीट पर जीत हासिल करते आए हैं।

चुनाव में कामत और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दामोदर शिरोड़कर को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में गणश्याम शिरोडकर को जीत हासिल हुई है। गणश्याम को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने समर्थन दे दिया। जबकि यह चुनाव सरदेसाई और कामत ने संयुक्त रूप से लड़ा था, जो दो साल पहले बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए थे।

महापौर चुनाव से पहले ही कामत कांग्रेस से अलग हो गए और सात अन्य विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। इसके बाद भी बीजेपी उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हो सकी। परिणाम स्पष्ट होने के बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कहा, ईश्वर और लोगों में हमारा विश्वास अटल हो। कोई भी परमेश्वर अनैतिकता और अधर्म को उचित नहीं ठहराएगा।

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की हार पर चुटकी ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा, 'गोवा क्रांति आंदोलन ऐतिहासिक शहर मडगांव से शुरू हुआ था। आज मडगांव के लोगों ने गोवा के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि जनादेश अलोकतांत्रिक भाजपा के खिलाफ है। मैं उन सभी 15 पार्षदों को बधाई देता हूं जिन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।'

भीमराव आंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं पीएम मोदी, रामनाथ कोविंद ने की जमकर तारीफ

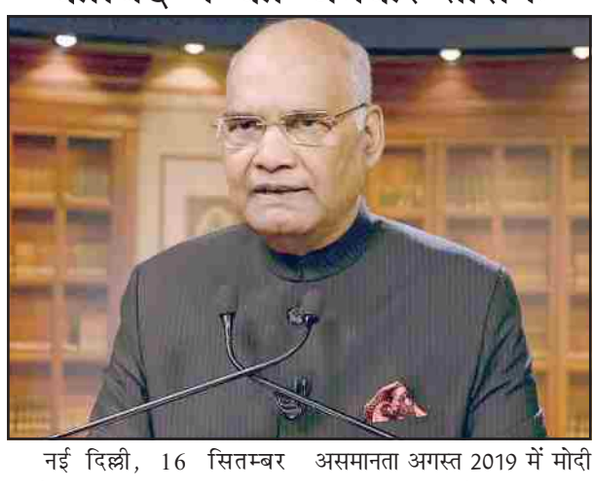

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (एजेन्सी)। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को भीमराव आम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बताया है। इसके साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति ने उन पहलुओं को भी गिनाया है जिनकी शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा, श्रमिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। अपने संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को आम्बेडकर के सपने के अनुरूप बताया है।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीमराव आम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और वह समाज सुधारक के सपनों को हकीकत में तब्दील करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि ये आम्बेडकर के सपने के अनुरूप ही किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, 'बाबासाहेब ने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बाद में, जटिल घटनाक्रम हुआ तो जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, जो बाबासाहेब की इच्छा के विरुद्ध था।' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में यह असमानता अगस्त 2019 में मोदी सरकार के प्रयासों के बाद खत्म कर दी गई।

कोविंद ने कहा, 'यह आदेश बाबासाहेब के आदर्शों को भी पूरा करता है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का मौका मिला।' पूर्व राष्ट्रपति ने 'आम्बेडकर एवं मोदी: रिफॉर्मर्स आईडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन' नामक किताब के विमोचन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि नेताओं के एक बड़े वर्ग ने कहा कि हमें कहना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हैं। लेकिन बाबासाहेब की सोच उच्च स्तर की थी।

कोविंद के मुताबिक, उन्होंने (आम्बेडकर) जोर देकर कहा कि हमें कहना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत तक भारतीय हैं। भारतीयता ही हमारी असली पहचान है और धर्म, जाति और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, 'नरेंद्र मोदी भी पहले भारत की बात करते हैं। जैसा कि बाबासाहेब ने कहा था कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय और अंत तक भारतीय हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पहले भारत कहते हैं। मोदी बाबासाहेब के सपनों को साकार कर रहे हैं।'

तिस्ता-6 जलविद्युत परियोजना में हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । तीस्ता-6 जलविद्युत परियोजना, सिक्किम में दिनांक 14 सितांबर को हिन्दी पखवाड़े की शुरुआत की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा परियोजना प्रमुख, तीस्ता-6 श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन किया

श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने इस अवसर पर सभी को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी एवं सभी से अपना अधिकाधिक कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में ही करने की अपील भी की हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 14 से 29 सितंबर तक की अवधि के दौरान तीस्ता-6 जलविद्युत परियोजना में विविध कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें कर्मचारियों से बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए परियोजना प्रमुख ने अपील भी की।

ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

पाकिम, 16 सितम्बर । अम्बा ताजा ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा आज बेरिंग जीपीके में आयोजित हुई। इस अवसर पर अपर बेरिंग पंचायत सदस्यों के अलावा एआरसीएस, एओ, सहकारिता विभाग के सीआई एवं कृषि निरीक्षक उपस्थित थे।

इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष ने सभी को सोसाइटी की परिसम्पत्तियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सदस्यों को एफपीओ के माध्यम से अपने उत्पादित फसलों की मार्केटिंग करने को कहा और एमसी की समस्याओं एवं अपने अनुभवों को साझा किया।

वहीं इस दौरान एओ द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गयी जिसमें उन्होंने एमसी को सोसाइटी द्वारा देखे जा रहे महत्वपूर्ण बुक ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया।

वहीं इस अवसर पर प्रबंधन समिति सदस्यों को उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कृषि अधिकारी ने सदस्यों को पीआईएस योजना के साथ किसानों के हितों के लिए चलायी जा रही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। एआरसीएस ने अपने वक्तव्य में सदन को एफपीओ के उद्देश्यों, सहकारी समितियों में पारदर्शिता के महत्व तथा सम्बंधित विभागों से समन्वय के बारे में जानकारी प्रदान की।

विधानसभा में बीजेपी विधायक ने की इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 सितम्बर । सिक्किम विधानसभा के आज आयोजित हुए एकदिवसीय सत्र में भाजपा ने राज्य एवं यहां के नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु इनर लाइन परमिट लागू करने की महत्वपूर्ण मांग उठायी। सत्र के दौरान अपर बुर्तुक के भाजपा विधायक डीआर थापा ने यह मांग उठाते हुए राज्य के सभी विधायकों एवं सांसदों से मिल कर इस पर फैसला लेने को कहा।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजू गिरी ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि संवेदनशील राज्य सिक्किम में दिनों दिन बढ़ रही घुसपैठ, बाहरी श्रमिकों में वृद्धि एवं पिछले दिनों कुछ बाहरी तत्वों द्वारा सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 371एफ के अंतर्गत दिये गये विशेष दर्जा के विरोध के मद्देनजर आज पार्टी विधायक डीआर थापा ने सदन में इनर लाइन परमिट की मांग उठायी है। उनके अनुसार पूर्वोत्तर के कई राज्यों की तरह ही सिक्किम में भी आईएलपी लागू करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी विधायकों एवं सांसदों से मिल कर केंद्र पर दबाव बनाने को कहा। उनके अनुसार सिक्किम के अस्तित्व रक्षा हेतु सभी को राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना होगा।

आज सदन में डीआर थापा ने दिल्ली के जंतर-मंतर में दो युवकों सिक्किम के खिलाफ की गयी बयानबाजी एवं अनुच्छेद 371एफ के विरोध की तीव्र निंदा की। उन्होंने इसके पीछे के लोगों की पहचान कर

उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग भी की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों की स्थिति सुधारने हेतु दूध का न्यूनतम दर 60 रुपए प्रति लीटर करने की भी मांग उठायी। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने राज्य के सभी विभागों में आर्थिक समस्या का मुद्दा उठाते हुए सभी से मिल कर केंद्र से आर्थिक पैकेज बढ़ाने की मांग करने का भी सुझाव दिया।

इसके अलावा पार्टी के मानेबुंग-देन्ताम विधायक एनके सुब्बा ने भी आज सदन में सिक्किम के 12 जातियों को मान्यता दिलाने हेतु राज्य सरकार से निर्णायक पहल करने की मांग की। वहीं गंगटोक के विधायक वाईटी लेख्चा ने राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए जनता को न्याय प्रदान करने की मांग उठायी। आज सदन में भाजपा के 10 विधायकगण मौजूद थे।

डियर साप्ताहिक लॉटरी कोलकाता की एक गृहिणी ने ₹1 करोड़ जीते

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता ने **04.08.2022** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नम्बर **43G 73646** है। "डियर लॉटरी से एक करोड़ रुपए की यह पुरस्कार राशि जीतकर मैं काफी उत्साहित हूं। मेरे परिवार के सदस्य भी काफी प्रसन्नचित्त हैं। मैं अपने जीवन में हमेशा बेहतर जिंदगी जीने के सपने देखा करती थी। यह बड़ी पुरस्कार राशि मेरे लंबे समय के सभी सपनों को पूरा करेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डियर लॉटरी को धन्यवाद। मैं सभी को, खासकर हर उम्र की महिलाओं को डियर लॉटरी खरीदने तथा जीवन में बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने की सलाह देती हूं।" विजेता ने कहा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com